समाचार एवं विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।

पीतम सिंह यादव
9999164275

नई दिल्ली एवं गौतमबुद्धनगर से प्रकाशित,लखनऊ,गाजियाबाद,मुजफ्फरनगर,मेरठ,हापुड़,बुलन्दशहर,बागपत,फरीदाबाद में एक साथ प्रसारित

दैनिक सांई मीडिया

विश्वास का प्रतीक

वर्ष : 16 अंक : 101 | गौतमबुद्धनगर संस्करण, शुक्रवार, 11 अप्रैल 2025 | पेज: 8 | मूल्य : 2 रूपये

संक्षिप्त समाचार

जदयू नेता की हत्या में संघ-भाजपा कार्यकर्ता दोषी, हाई कोर्ट ने पलटा पिछला फैसला; सुनाई उम्रकैद

तिरुअनंतपुरम, एजेंसी। केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 2015 में जदयू नेता दीपक की हत्या के मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़े पांच कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सत्र न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया जिसमें इन आरोपियों को बरी कर दिया गया था। यह फैसला न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति जोबिन सेबेस्टियन की खंडपीठ ने सुनाया। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने साक्ष्यों को नजरअंदाज किया और ऐसे तथ्यों पर भरोसा किया जो इस मामले से अप्रासंगिक थे। कोर्ट ने चेताया कि ऐसे फैसले न्याय प्रणाली को कमजोर करते हैं और समाज में खतरनाक संदेश भेजते हैं कि गंभीर अपराधों में लिप्त लोग आसानी से बच सकते हैं। पीठ ने साफ कहा, अगर दोषियों को तकनीकी आधार पर छोड़ा गया तो यह समाज में अराजकता फैलाने वाला संकेत होगा। न्यायपालिका पर जनता का भरोसा ऐसे फैसलों से डगमगा सकता है। इससे पहले सत्र अदालत ने इस हत्याकांड में शामिल सभी 10 आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार और मृतक की पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पांच आरोपियों- ऋषिकेश, निजिन उर्फ कुंजप्पू, प्रशांत उर्फ कोचू, रसंत और ब्रशनेव को दोषी ठहराया। इन सभी को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 34 (सामूहिक इरादा) के तहत दोषी माना गया और आजीवन कारावास के साथ-साथ एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जिन दो दोषियों को पहले से ही आजीवन कारावास मिला हुआ है, उन्हें यह सजा साथ-साथ चलाने की छूट मिली है। वहीं, बाकी पांच आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी करने के सत्र अदालत के फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। दीपक जदयू के स्थानीय नेता थे और त्रिशूर जिले के पझुविल क्षेत्र में राशन दुकान चलाते थे। उनकी हत्या के पीछे कथित रूप से राजनीतिक रंजिश मानी जा रही है।

सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किए 67 करोड़ रुपये लागत की कई विकास परियोजनाएं

कोच्चि, एजेंसी। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को कोच्चि स्थित इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी (आईएमयू) परिसर में 67.77 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने कोच्चि में नए गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला रखी और अन्य पांच आईएमयू परिसरों में परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। इन परिसरों में चेन्नई, कोलकाता, नवी मुंबई, मुंबई पोर्ट और विशाखापत्तनम शामिल हैं। इन परियोजनाओं में अत्याधुनिक सिम्युलेटर, सोलर पावर प्लांट्स, खेल सुविधाओं में सुधार और छात्रावासों का नवीनीकरण शामिल है। वहीं गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण पर 13.11 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एर्नाकुलम के सांसद हिबी ईडन, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के एमडी सुनील मुकुंदन, ढूरू की कुलपति डॉ. मालिनी वी. शंकर और कई अन्य अधिकारी एवं शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने कहा, ये 17 परियोजनाएं भारत की समुद्री शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक मजबूत कदम हैं। इससे छात्रों को आधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी। इससे पहले सोमवार को मंत्री सोनोवाल ने देश की जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री 4.0-रेडी अत्याधुनिक मशीनरी का उद्घाटन किया। उन्होंने ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत दो ग्रीन टग्स के निर्माण के लिए स्टील कटिंग समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह भारत के आत्मनिर्भर और हरित समुद्री भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है।

आ गया तहव्वुर राणा, अब आगे क्या होगा, मोदी का प्लान तैयार!

नई दिल्ली। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा अमेरिका से प्रत्यर्पित होने के बाद एक विशेष विमान से भारत आ गया है। दिल्ली

एक शख्स को इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भूला नहीं जा सकता है और वो अजित डोभाल हैं। जिनसे पाकिस्तान थर थर कांपता है। जिनकी वजह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अजित डोभाल की अगुवाई में लगातार मीटिंग की गई औड़ कैसे प्रत्यर्पण के बाद राणा को भारत लाया जाएगा, क्या क्या रणनीति होगी।

एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसे एनआईए द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसका मेडिकल टेस्ट होगा। एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। सवालों की एक लंबी फेहरिस्त है। इस पूछताछ को बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं। एनआईए की जब चार्जशीट हुई थी तो उसमें डेविड कॉलमैन हेडली और तहव्वुर राणा दो ऐसे 26/11 हमले के आरोपी थे, जो अमेरिका की जेल में बंद थे। बाकी सात आरोपी पाकिस्तान में अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। इनमें से कई आईएसआई के मेजर रैंक के अधिकारी का नाम भी सामने आया था। इसे भी पढ़ें: आतंकियों पर भारत के तगड़े एक्शन से खुश हुआ इजरायल, बोला- थैक्यू मोदी सरकार एक शख्स को इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भूला नहीं जा सकता है और वो अजित डोभाल हैं। जिनसे पाकिस्तान थर थर कांपता है। जिनकी वजह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अजित डोभाल की अगुवाई में लगातार मीटिंग की गई औड़ कैसे प्रत्यर्पण के बाद राणा को भारत लाया जाएगा, क्या क्या रणनीति होगी। कूटनीतिक जो जीत हुई है वो दिलाने में डोभाल का अहम योगदान है। पूछताछ में क्या होगा और पाकिस्तान को कैसे बेनकाब किया जाएगा। अजित डोभाल तमाम रणनीति तय कर रहे हैं और पल पल पर उनकी नजर है। फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ह्यव्हाइट हाउसह्ल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि उनके प्रशासन ने ह्यदुनिया के सबसे बुरे व्यक्तिह्ल राणा को भारत में न्याय का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है।

कसाब को कांग्रेस ने बिरयानी खिलाई, राणा को भारत की धरती पर मिलेगी सजा, पीयूष गोयल बोले- देश को मोदी जी पर गर्व है

नई दिल्ली। 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा को आज भारत प्रत्यर्पित किए जाने के साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस की तीखी आलोचना करते हुए और न्याय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए राजनीतिक तूफान को फिर से हवा दे दी है। गोयल ने पूर्व यूपीए सरकार पर आतंकवादी अजमल कसाब के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने उसे बिरयानी खिलाई, जबकि इसकी तुलना पीएम मोदी की अपराधियों को जवाबदेह ठहराने की प्रतिबद्धता से की। गोयल ने कहा कि ताज होटल पर आतंकवादी हमला कांग्रेस की निगरानी में हुआ। निर्दोष लोगों की जान चली गई, लेकिन वे कार्रवाई करने में विफल रहे। इसके बजाय, उन्होंने कसाब के साथ नरमी बरती। यह मोदी जी का संकल्प ही था जिसने हमें आखिरकार आज तक पहुंचाया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) पर भी निशाना साधा और उस पर राष्ट्रीय हित के बजाय तुष्टीकरण को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संजय राउत किसी भी मुस्लिम का बचाव करेंगे, चाहे वह किसी गंभीर अपराध में शामिल क्यों न हो। पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के विपरीत, भारत का गुट वोट बैंक की राजनीति में फंसा हुआ है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा के आज दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी है। एक बहु-एजेंसी केंद्रीय टीम उन्हें लेकर जा रही है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) उनके पहुंचने पर उन्हें हिरासत में ले लेगी।

सूत्रों का कहना है कि राणा को बाद में पूछताछ के लिए मुंबई ले जाया जा सकता है, संभवतः बायकुला जेल में प्रॉपर्टी सेल कार्यालय या मुंबई पुलिस के यूनिट 1 मुख्यालय में। उन्हें आर्थर रोड जेल में बैरक नंबर 12 में रखे जाने की संभावना है - वही उच्च सुरक्षा वाली कोठरी जिसमें कभी अजमल कसाब को उसके मुकदमे और फांसी के दौरान रखा गया था।

1 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ वक्फ कानून प्रस्ताव, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने लिया फैसला

नई दिल्ली। प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वक्फ कानून के खिलाफ एक करोड़ लोगों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव भेजने की कसम खाई है। कोलकाता के रामलीला मैदान में एक विशाल सभा में जमीयत के बंगाल चैप्टर ने अपने प्रमुख और मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से इस कानून को तुरंत निरस्त करने का आग्रह किया। जमीयत ने वक्फ कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए क्राउडफंडिंग अभियान की भी घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते कई याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। कानून के खिलाफ हस्ताक्षर स्वयंसेवक बंगाल के विभिन्न जिलों में जाकर एकत्र करेंगे। चौधरी ने कहा कि इस तरह के सामूहिक आंदोलन के कारण पहले भी सरकारों ने कानून वापस लिए हैं। हमारा लक्ष्य विभिन्न जिलों और कस्बों से ये हस्ताक्षर प्राप्त करना और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को भेजना है। चौधरी ने सभा को बताया कि पहले भी कानून वापस लिए गए हैं और इस कानून को निरस्त करवाने के लिए हम 1 करोड़ हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। वक्फ कानून, जिसे पिछले सप्ताह संसद द्वारा आधी रात के बाद तक चली बैठकों में पारित किया गया था, वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने और उनसे संबंधित विवादों का निपटारा करने में सरकारी निगरानी का विस्तार करता है। जमीयत ज्ञापन में कहा गया है कि वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसमें कहा गया है कि यह कानून वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता को कमजोर करता है और नौकरशाहों को अत्यधिक अधिकार देकर अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र का इरादा वक्फ प्रशासन पर नियंत्रण करना और मुस्लिम समुदाय को अपने धार्मिक बंदोबस्त के प्रबंधन से अलग करना है। मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग द्वारा विरोध किए जाने वाले प्रावधानों में से एक केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को अनिवार्य रूप से शामिल करना है। कानून का एक और विवादास्पद प्रावधान यह है कि यह राज्य के अधिकारी को यह निर्धारित करने का अधिकार देता है कि विवादित संपत्ति वक्फ है या सरकार की है।

झुलसाने वाली गर्मी से मिली बड़ी राहत

Delhi-NCR के कई इलाकों में धूल भरी आंधी और बारिश

नई दिल्ली। मौसम में अचानक आए बदलाव के चलते दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में गुरुवार को धूल भरी आंधी और मध्यम बारिश देखी गई। मौसम विभाग ने आज दिन में बारिश और आंधी की भविष्यवाणी की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस, दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, पंजाबी बाग, सीलमपुर, शाहदरा, लाल किला और प्रीत विहार जैसे इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा कि हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम और छपरौला जैसे एनसीआर के इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है।

इसके बाद दिल्ली एनसीआर में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। आईएमडी के अनुसार, अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहने पर तथा न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने पर "गर्म रात" घोषित की जाती है। न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर "बहुत गर्म रात" घोषित की जाती है। वहीं, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बृहस्पतिवार को बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि होने, आंधी आने और बिजली गिरने की घटना से फिरोजाबाद, सिद्धार्थ नगर और सीतापुर में पांच लोगों की मौत हो गई।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को प्रभावित इलाकों का दौरा करने और प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अपर जिलाधिकारी विशू राजा ने बताया कि बिजली गिरने की पहली घटना तहसील सदर क्षेत्र नारखी थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर में घटी जिसमें खेत पर काम कर रही महिला ललिता देवी (30) की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। दूसरी घटना थाना जसराना क्षेत्र के गांव चनारी की है जहां खेत पर काम कर रहे किसान पदम वीर सिंह (32) की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई।

गुरदासपुर में चौतरा बीएसएफ पोस्ट पर ब्लास्ट

गुरदासपुर (एजेंसी)। पंजाब के गुरदासपुर में बीओपी चौतरा बॉर्डर के पास कंटीली तारों के पार हुए हुए ब्लास्ट में बीएसएफ का जवान जख्मी हुआ है। बीएसएफ सेक्टर के पास हुई इस संदिग्ध घटना से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। घटनास्थल पर जांच के लिए बीएसएफ के अधिकारी पहुंच गए हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात बीएसएफ की चौतरा बीओपी के जवान कंटीली तार के पास ड्यूटी पर तैनात थे, तभी एक विस्फोट हुआ और बीएसएफ जवान का पैर जख्मी हो गया। घटना की खबर सुनकर बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और गहन जांच शुरू की। घायल जवान को इलाज के लिए अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सारे मामले को लेकर बीएसएफ और पंजाब पुलिस का कोई भी बयान सामने नहीं आया है।

गलियारे में सऊदी अरब समेत कई देश,रफ्तार देने जा रहे पीएम मोदी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी अप्रैल के तीसरे सप्ताह में सऊदी अरब जा सकते हैं। अभी तारीखों पर अंतिम फैसला होना बाकी है, लेकिन उनका दौरा करीब-करीब तय हो गया है। दो दिनों का उनका यह दौरा होगा, जिसमें वह सऊदी अरब के नेताओं के साथ कारोबार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा संबंधों को लेकर बात करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा एजेंडा इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर भी होगा। इस पर जी-20 समिट के दौरान सहमति बनी थी और

Digital Data Protection Act: विपक्ष के आरोपों को सरकार ने किया खारिज, अश्विनी वैष्णव ने कही बड़ी बात

नई दिल्ली। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के इस दावे को खारिज कर दिया है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 सूचना के अधिकार अधिनियम को कमजोर करता है। एक विस्तृत पत्र में, वैष्णव ने स्पष्ट किया कि डेटा संरक्षण अधिनियम, आरटीआई अधिनियम, 2005 में निर्धारित पारदर्शिता के सिद्धांतों के साथ पूर्ण सामंजस्य में है, और नागरिकों के सूचना के अधिकार को खत्म नहीं करता है। मंत्री की प्रतिक्रिया जयराम रमेश द्वारा सरकार से डेटा संरक्षण अधिनियम की धारा 44 (3) को रोकने, समीक्षा करने और निरस्त करनेह्व का आग्रह करने के बाद आई, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) में प्रावधान को खत्म कर देगा। रमेश के अनुसार, इससे जनता की सूचना तक पहुँच, खास तौर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के बारे में, बहुत कमजोर हो जाएगी। वैष्णव ने हालाँकि कहा कि नया अधिनियम सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता की आवश्यकता के साथ निजता के अधिकार को सावधानीपूर्वक संतुलित करता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक पुट्टस्वामी फैसले का हवाला दिया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पुष्टि की गई थी।उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अधिकार व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है और इसे जनता के सूचना के अधिकार के साथ सह-अस्तित्व में रहना चाहिए। मंत्री ने कहा कि डेटा संरक्षण अधिनियम की धारा 3 किसी भी कानूनी दायित्व के तहत व्यक्तियों द्वारा पहले से ही सार्वजनिक किए गए व्यक्तिगत डेटा को छूट देती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मनरेगा जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित डेटा और जन प्रतिनिधियों से संबंधित कानूनों के तहत खुलासा किए जाने वाली जानकारी आरटीआई ढांचे के तहत सुलभ रहेगी। वैष्णव ने जोर देकर कहा कि कानून को अंतिम रूप देने से पहले नागरिक समाज समूहों और संसदीय मंचों के साथ बातचीत सहित व्यापक परामर्श किया गया था।विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बृहस्पतिवार को ह्यडिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम की धारा 44(3) को निरस्त करने की मांग करते हुए दलील दी कि यह सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून को कमजोर करती है।

किसी भी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने पर रोक लगाने वाली धारा और आरटीआई अधिनियम पर इसके प्रभाव को लेकर नागरिक समाज समूहों द्वारा चिंता जताए जाने के बीच, विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि जब यह अधिनियम लोकसभा में पारित किया जा रहा था, तब सरकार ने इसमें कुछ संशोधन पेश किए, जिससे विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की सिफारिशों को पलट दिया गया।

आतंकियों पर भारत के तगड़े एक्शन से खुश हुआ इजरायल, बोला- थैक्यू मोदी सरकार

नई दिल्ली। इजराइल ने पाकिस्तानी-कनाडाई आतंकवादी तहव्वुर राणा और मुंबई 26/11 हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा के अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण के कमद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इजराइल ने 26/11 के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का स्वागत किया है। भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर इस घटनाक्रम का स्वागत किया। अजार ने एक वीडियो संदेश में कहा ति मैं आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत सरकार की दृढ़ता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को बृहस्पतिवार को विशेष विमान से भारत लाए जाने की संभावना है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पाकिस्तानी मूल के 64 वर्षीय कनाडाई नागरिक राणा को लॉस एंजिलिस के मेट्रोपोलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। अधिकारियों ने बताया कि एक बहु-एजेंसी टीम अमेरिका गई है और राणा को भारत लाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ सभी कागजी कार्रवाई और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। प्रत्यर्पण से बचने के राणा के आखिरी प्रयास के विफल होने के बाद उसे भारत लाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, आप सभी जानते हैं कि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी है।

राणा को पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा माना जाता है, जो 26/11 के मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकताओं में से एक है। 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने अरब सागर में समुद्री मार्ग से भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में घुसपैठ करने के बाद एक रेलवे स्टेशन, दो आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर हमला किया था। साल 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में छह अमेरिकियों समेत कुल 166 लोग मारे गए थे। इन हमलों को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। नवंबर 2012 में, पाकिस्तानी समूह के एकमात्र जीवित आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को पुणे की यरवदा जेल में फांसी दे दी गई थी। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि राणा ने हेडली को भारत के लिए वीजा दिलाने में मदद की थी।

जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग एक्टिव

यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत सवारियों की ओवर लोडिंग करने पर 05 बसों का चालान कर किया गया निरुद्ध

सांई मीडिया ब्यूरो

*गौतम बुद्ध नगर 10 अप्रैल जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निदेर्शों के क्रम में परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सवारीयों की ओवर लोडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन डा उदित नारायण पाण्डेय ने बताया कि आज सवारियों की ओवर लोडिंग करने वाली 05 बसों का चालान कर निरुद्ध किया गया है।

उन्होंने बताया कि सवारी वाहनों और बसों में ओवरलोडिंग के कई नुकसान हो सकते हैं, जो न केवल यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, बल्कि सड़क यातायात और पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं।

ओवरलोडिंग के नुकसानः

सुरक्षा पर खतराः वाहन की क्षमता से अधिक सवारियों के कारण ब्रेक, टायर और

सस्पेंशन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। आपातकालीन स्थिति में वाहन को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। सवारियों के लिए निकासी का स्थान कम होने से हादसे में जानमाल का नुकसान बढ़ सकता है।

वाहन की क्षतिः

ओवरलोडिंग से वाहन के पुर्जों (जैसे इंजन, टायर, ब्रेक) पर अतिरिक्त भार पड़ता है, जिससे उनकी आयु कम हो जाती है और रखरखाव का खर्च बढ़ जाता है।

ईंधन की बबार्दीः

अधिक वजन के कारण वाहन को चलाने में ज्यादा ईंधन खर्च होता है, जो आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टि से नुकसानदायक है।

यात्रियों के लिए असुविधाः

भीड़भाड़ के कारण यात्रियों को बैठने या खड़े होने में परेशानी होती है, जिससे यात्रा थकाऊ और असुरक्षित बन जाती है।

कानूनी परिणामः

ओवरलोडिंग यातायात नियमों का उल्लंघन है, जिसके लिए जुमार्ना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

अपीलः

उन्होंने सभी वाहन चालकों, मालिकों और यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि सवारी वाहनों और बसों में ओवरलोडिंग से बचें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए वाहन की निर्धारित क्षमता का पालन करें। यह न केवल दुर्घटनाओं को रोकेगा, बल्कि सड़कों को सुरक्षित और यात्रा को सुखद बनाएगा। आइए, हम सब मिलकर जिम्मेदार नागरिक बनें और यातायात नियमों का सम्मान करें। सुरक्षित यात्रा, स्वस्थ जीवन!

ग्रेटर नोएडा टू गाजियाबाद के बीच नहीं मिलेगा जाम

ग्रेटर नोएडा एजेंसी। गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। एनएच नौ से शाहबेरी के बीच लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए नए नाले पर सड़क बनाने की तैयारी है। पहले करीब दो किलोमीटर लंबा नाला बनाया जाएगा। इसके ऊपर ही सड़क का भी निर्माण किया जाएगा। इससे लोगों को राहत मिल सकेगी।

क्रॉसिंग रिपब्लिक में करीब 29 सोसाइटियां हैं, जिसमें एक लाख से अधिक लोग रहते हैं। एनएच नौ से क्रॉसिंग रिपब्लिक होते हुए ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले शाहबेरी मार्ग की चौड़ाई कम है। इस कारण इस मार्ग पर हर वक्त जाम की समस्या झेलनी पड़ती है। सबसे अधिक जाम सुबह और शाम को लगता है।

इस समस्या को दूर करने के लिए अब नगर निगम ने एक योजना तैयार की है। इसके तहत नाले के ऊपर सड़क बनाई जाएगी। इससे एनएच नौ से शाहबेरी तक सड़क के 45 मीटर चौड़ी होने की उम्मीद है। ऐसे में क्रॉसिंग रिपब्लिक और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लोगों को सहूलियत मिलेगी। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, इस मार्ग के बराबर में नाला बहता है, लेकिन फिर भी क्षेत्र में जलनिकासी की समस्या है। इसे दूर करने के लिए नाले का निर्माण किया जाएगा। साथ ही, इस नाले के ऊपर करीब दो किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी, ताकि वाहन चल सकें और इस मार्ग पर लगने वाले जाम को दूर किया जा सके। अधिकारी बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट तैयार कर शासन को भेजा गया है, जिसके बाद शासन स्तर पर दो बैठक भी हो चुकी है। आगामी बैठक में इस परियोजना को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट पर 132 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस मार्ग के बीच में 12 खंभे हैं। शहर विधायक संजीव शर्मा ने बताया कि वे जीडीए टीम के साथ अगले हफ्ते मौके का निरीक्षण करेंगे, जिसमें सड़क के बीच लगे खंभों को हटाने की योजना बनाई जाएगी। इन खंभो के हटने से जाम की समस्या काफी हद तक दूर होगी, फिर नाले के ऊपर सड़क का निर्माण से राहत मिलेगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एकमूर्ति चौक से राष्ट्रीय राजमार्ग नौ तक एलिवेटड रोड बनाने की योजना है। चार किलोमीटर लंबी और चार लेन की एलिवेटेड रोड शाहबेरी होते हुए बनाई जाएगी।

पुरानी संपत्तियों से भी वसूला जाएगा डेढ़ गुना हाउस टैक्स, साढ़े 4 लाख पर बढ़ेगा बोझ; गाजियाबाद निगम का फैसला

गाजियाबाद एजेंसी। गाजियाबाद नगर निगम इस वित्त वर्ष से पुरानी संपत्तियों पर भी डीएम सर्किल रेट का डेढ़ गुना गृहकर वसूलेगा। इस संबंध में निगम ने शासन से सुझाव मांगे थे। शासन ने नगर आयुक्त को जवाब भेजकर अवगत कराया कि वह अपने स्तर से सर्किल रेट से कर निर्धारित कर सकते हैं। इस फैसले से करीब साढ़े चार लाख लोगों पर बोझ बढ़ेगा।

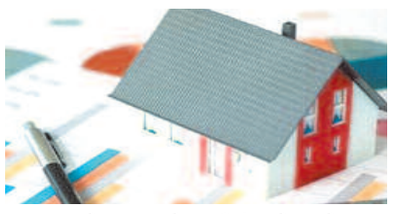

शहर में कुल छह लाख करदाता हैं। इनमें साढ़े चार लाख पुरानी और डेढ़ लाख नई संपत्तियां हैं। नई संपत्तियों पर पहले ही टैक्स बढ़ाया जा चुका है। नगर निगम ने वर्ष 2024 डीएम सर्किल रेट से गृहकर बढ़ाने का प्रस्ताव सदन की बैठक में रखा था। दो बार यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। इसके बाद निगम ने प्रस्ताव शासन में भेज दिया था। साथ ही, नगर आयुक्त ने शासन से गृहकर बढ़ोतरी पर सुझाव मांगे थे। अब नगर विकास अनुभाग-9 के अनु सचिव मोहम्मद वासिफ ने जवाब भेजा है।

जवाब के अनुसार, नगर आयुक्त हर दो साल में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण या डीएम द्वारा तय सर्किल रेट और ऐसे भवन या भूमि के लिए उस क्षेत्र में किराये की वर्तमान न्यूनतम दर से कर टैक्त तय कर सकते हैं। निगम ने इस वित्त वर्ष से पुरानी संपत्तियों पर डीएम सर्किल रेट का डेढ़ गुना गृहकर वसूलने की तैयारी कर ली है, क्योंकि निगम नई संपत्ति से डेढ़ गुना बढ़ाकर हाउस टैक्स वसूलने लगा है।

पूर्व एसएचओ सहित 12 पुलिसवालों पर एफआईआर, बीटेक छात्र के फर्जी एनकाउंटर का आरोप

नोएडा एजेंसी। नोएडा में बीटेक के छात्र को फर्जी मुठभेड़ में गोली मारने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर जेवर थाने के पूर्व एसएचओ समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जेवर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में पूर्व एसएचओ के साथ छह दरोगा और पांच कॉन्स्टेबल भी नामजद किए गए हैं। छात्र के पिता ने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए कोर्ट में शिकायत की थी।

मथुरा के कदम्ब विहार निवासी तरुण गौतम का आरोप है कि चार सितंबर 2022 को बिना नंबर की दो कार उनके घर पर आईं। कारों से उतरे लोगों ने उनसे बेटे सोमेश गौतम के बारे में पूछा। इस पर उन्होंने बताया कि वह कोटा राजस्थान से बीटेक कर रहा है और दिल्ली में तीन महीने के लिए कोचिंग के लिए गया है। यह बताने पर कारों से आए लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जबरन कार में बैठाकर अपने साथ ले गए।

पीड़ित तरुण गौतम के अनुसार, देर रात वह उसे लेकर सोमेश के दिल्ली स्थित कमरे पर पहुंचे और वहां उससे मारपीट कर गाड़ी में डाल लिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल्ली से लाने के बाद सोमेश को जेवर थाने में रखकर मारपीट की गई और करंट लगाया गया। फिर पुलिस ने 6 सितंबर 2022 की रात में मुठभेड़ दिखाते हुए सोमेश को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया और उससे एक बाइक और पिस्टल भी बरामद दिखा दी। उन्हें धमकी दी गई कि यदि किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे।

बेटे के साथ मुठभेड़ के बाद उन्हें भी छोड़ने के लिए एक लाख रुपये मांगे गए। रुपये लेने के बाद ही उन्हें छोड़ा गया। बेटे पर बाद में गैंगस्टर ऐक्ट की धारा भी लगा दी गई। पिता का आरोप है कि बेटे की जमानत कराने और उसका इलाज कराने के बाद वह लगातार इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया।

सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में 14 फरवरी 2025 को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने आदेश में लिखा था कि विपक्षी लोकसेवक है। इसके चलते केस दर्ज करने से पहले पुलिस कमिश्नर से अनुमति प्राप्त करना अति आवश्यक है। कमिश्नर से अनुमति मिलने के बाद मंगलवार को इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। पिता तरुण गौतम ने कोर्ट में छात्र को दिल्ली से पुलिस द्वारा पकड़कर हिरासत में लेने की सीसीटीवी फुटेज भी जमा कराई थी। नीमका गांव में एक सितंबर 2022 को हिस्ट्रीशीटर नागेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नागेश को सुंदर भाटी गैंग का सदस्य बताया गया था। नागेश के भाई ने नीमका गांव निवासी चमन, देवराज, उमेश को नामजद कर कुल 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसी हत्याकांड में सोमेश को भी आरोपी बताया गया था। पुलिस ने चमन, सोमेश गौतम, प्रवीण, दिलीप, जितेंद्र विजय विकास पर गैंगस्टर लगाया था।

जेवर के तत्कालीन थानाध्यक्ष अंजनि कुमार, सब-इंस्पेक्टर राकेश बाबू, सब-इंस्पेक्टर अनिरुद्ध यादव, सब-इंस्पेक्टर चांदवीर सिंह, सब-इंस्पेक्टर शरद यादव, सब-इंस्पेक्टर सन्नी कुमार, सब-इंस्पेक्टर नीलकांत और कॉन्स्टेबल सोहित कुमार, भूरी सिंह, जयप्रकाश, नौस कुमार और छीतर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।

साद मियां खां, डीसीपी ग्रेटर नोएडा ने कहा, इस मामले में पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज हुआ है। पूर्व में वादी की ओर से दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में भी प्रार्थनापत्र दिया गया था, लेकिन वहां खारिज हो गया था। मुकदमे में नामजद कई पुलिस कर्मी इस समय जिले से बाहर हैं। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है।

स्कूल ने नहीं दी एंट्री, गाजियाबाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पैरेंट्स; बच्चों ने परिसर में ही शुरू की पढ़ाई

गाजियाबाद एजेंसी। गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है। स्कूल बढ़ी हुई फीस नहीं देने पर 15-20 बच्चों को एंट्री नहीं दे रहा है। ऐसे में बुधवार को अभिभावक बच्चों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी से बच्चों को स्कूल में एंट्री दिए जाने की मांग की है। इस दौरान छात्रों ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही पढ़ाई शुरू कर दी। बीते दो दिनों से अभिभावक स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को भी दो घंटे हंगामा चला लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।

सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल ने नया सत्र शुरू होने से पहले 108

बच्चों को नोटिस दिया था कि फीस न भरने पर नाम काटा जा सकता है। अभिभावकों का कहना था कि 2018-19 के बाद दाखिला लेने वाले इन बच्चों की मनमानी फीस बढ़ा दी गई, जो जिला शुल्क नियामक समिति की निर्धारित फीस से कहीं अधिक है। इसीलिए अभिभावक फीस नहीं दे रहे हैं। रविवार को जिलाधिकारी आवास पर प्रदर्शन किया और सोमवार को बच्चे स्कूल पहुंचे तो इन बच्चों को प्रवेश नहीं मिला।

अभिभावक अपर्णा शुक्ला का कहना है कि मंगलवार को भी स्कूल ने बच्चों को प्रवेश नहीं दिया। सुबह साढ़े सात बजे अभिभावक पहुंचे तब भी गेट नहीं खोला। इसीलिए 100 से अधिक अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। इसी बीच स्कूल प्रबंधन ने चार अभिभावकों को बुलाकर कहा कि फीस उतनी ली जाएगी। गतिरोध चलता रहा। वहीं, स्कूल में प्रवेश न मिलने और दो दिन से चल रहे हंगामे को देख कई बच्चों की आंखे छलक पड़ीं।

जयपुरिया पैरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण कुमार का कहना है कि स्कूल प्रबंधन यूपी स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क निर्धारण अधिनियम 2018 की जिस धारा में फीस बढ़ा रहा है, उसी धारा में लिखा है कि यदि कोई शासनादेश आया हो तो उसके अनुरूप फीस बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद भी डीएफआरसी का उल्लंघन किया जा रहा है।

तमिलनाडु में राज्यपाल पर गरमाई सियासत

चेन्नई, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को राज्य विधानसभा में पारित 10 विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं देने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। अब राज्य में उन्हें हटाने और इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। कांग्रेस, वीसीके, मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, वामपंथी दलों और अन्य सहयोगियों सहित सत्तारूढ़ द्रमुक के नेताओं ने राज्यपाल की कार्रवाई को माफ करने के एससी के फैसले की सराहना की। साथ ही, इस संबंध में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की। राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि राज्यपाल को अब पद पर बने नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उनके समक्ष लंबित सभी विधेयकों को उनकी सहमति प्राप्त हो गई है। उन्होंने मांग की कि राज्यपाल को या तो वापस बुलाया जाए, पद से हटाया जाए या फिर उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पीएमके और अभिनेता विजय की टीवीके के नेताओं ने भी उच्चतम न्यायालय के आदेश की सराहना की। साथ ही, इसे राज्य की स्वायत्तता और संघवाद के लिए ऐतिहासिक जीत बताया है। द्रमुक कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर फैसले का जश्न मनाया।

25 हजार सैलरी, फिक्स टारगेट; दिल्ली के जनकपुरी में कॉल सेंटर से चलता था ठगी का कारोबार

फरीदाबाद एजेंसी। फरीदाबाद के साइबर थाना सेंट्रल की पुलिस ने मंगलवार दोपहर दिल्ली के जनकपुरी स्थित एक किराए के फ्लैट में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 11 युवतियों समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 15 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए हैं। कॉल सेंटर बीते छह महीने से चलाया जा रहा था। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार गिरफ्तार आरोपी दिल्ली दक्षिण-पश्चिम के निवासी बताए जाते हैं। इनकी पहचान साक्षी नेगी, दीपिका, बबीता, समरा, प्रिया मेहरा, कोमल, ज्योति भारती, अमिसा, सोनम कौर, परमीत कौर, नांगलोई के अब्दुल वाहिद और बिहार निवासी चंचल के रूप में हुई है। गिरफ्तार लोगों की फोटो फरीदाबाद पुलिस ने मुहैया कराई है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी और कॉल सेंटर संचालक बिहार के पूर्णिया निवासी खुशहाल उर्फ रौनक की तलाश की जा रही है। आरोपियों के पास से 15 मोबाइल फोन और 12 डिवाइस आदि बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मंगलवार को आरोपियों को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए पांच दिन की रिमांड पर लिया है । मास्टर माइंड की गिरफ्तारी से और भी खुलासे होने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से बरामद मोबाइल फोन की जांच की जा रही है। साथ ही उनके बैंक खातों की डिटेल भी निकाली जा रही है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने देशभर के करीब 105 लोगों से ठगी की है। सभी को क्रेडिट कार्ड की लिमिट आदि को बढ़ाने का झांसा देते थे और खाता हैक कर रकम निकाल लेते थे। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बल्लभगढ़ स्थित श्याम कॉलोनी

निवासी एक व्यक्ति ने बीते दिन शिकायत दी थी। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि उनके मोबाइल फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले अपने-आपको एक बैंक का कर्मचारी बताया। साथ ही क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा दिया। साथ ही आरोपियों ने मोबाइल फोन पर भेजा गया ओपीटी नंबर पूछकर क्रेडिट कार्ड से दो बार में करीब 83 हजार रुपये निकाल लिए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी थी।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से सात ने स्नातक तक की पढ़ाई की है। बाकी दसवीं-बारहवीं पास हैं। मास्टरमाइंड खुशहाल गिरफ्तार सभी आरोपियों करीब 25 हजार मासिक वेतन देता था। इसके अलावा सभी को ठगी करने का टारगेट फिक्स था। एक को कम से कम तीन लोगों से ठगी करने का टारगेट दिया जाता था। फर्जी कॉल सेंटर का मास्टरमाइंड बिहार के पूर्णिया का खुशहाल उर्फ रौनक है। उसकी अनुपस्थिति में अब्दुल वाहिद और चंचल चलाता था। खुशहाल जनकपुरी में किराए पर फ्लैट लेकर मार्च-2024 से कॉल सेंटर चला रहा था। वह क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने, हेल्थ इंश्योरेंस व क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड्स पॉइंट्स आदि का झांसा देकर ठगी करता था।

गौरतलब है कि नौ मार्च को भी साइबर थाना की पुलिस ने दिल्ली में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया था। आठवीं पास नितेश कुमार ठाकुर दिल्ली के पीरागढ़ी में कॉल सेंटर चला रहा था। पुलिस ने मालिक और दो महिला समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 14 मोबाइल फोन व अन्य सामान बरामद किए गए थे।

सौर ऊर्जा और गेहूं क्रय में बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना और रबी विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत गेहूं खरीद की संयुक्त समीक्षा बैठक

सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत राज्य में कम लागत की विश्वसनीय सौर ऊर्जा तक आम लोगों की पहुंच को सुनिश्चित किया गया है: मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश ने सोलर पॉलिसी के तहत 2027 तक सोलर प्रोडक्शन में 22 हजार मेगावाट से अधिक का लक्ष्य निर्धारित किया: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को अभियान चलाकर सोलर पैनल वितरण के दिए निर्देश
सोलर रूफटॉप की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने आवश्यकता के अनुरूप वेंडर्स की संख्या में वृद्धि करने के भी दिए निर्देश
पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को भी अभियान चलाकर सोलर पैनल से आच्छादित किया जाए: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री का निर्देश- प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में सोलर पार्क विकसित किए जाएं, इसके लिए नगर निगम भूमि उपलब्ध कराएं
कृषकों से गांव में संपर्क कर निर्धारित एमएसपी से अवगत कराते हुए क्रय केंद्रों पर गेहूं लाने के लिए किया जा रहा प्रेरित: मुख्यमंत्री
भारत सरकार की अनुमति के फलस्वरूप कृषकों से संपर्क कर उनके गांव/दरवाजे पर जाकर भी गेहूं क्रय कराया जा रहा: मुख्यमंत्री
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय योजनाओं में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री जी को दी बधाई
प्रदेश सरकार बढ़ती ऊर्जा मांगों के अनुरूप कार्य करते हुए पूरे देश के लिए मॉडल बनेगी: प्रहलाद जोशी

सांई मीडिया ब्यूरो

लखनऊ, 10 अप्रैल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत सरकार के कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एवं पीएम कुसुम योजना और रबी विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत गेहूं खरीद को लेकर संयुक्त समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री का अपने सरकारी आवास पर स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी और गेहूं खरीद में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश अपनी ओर से बेस्ट रिजल्ट देने का प्रयास करेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने भी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई दी और कहा कि प्रदेश सरकार बढ़ती ऊर्जा मांगों के अनुरूप कार्य करते हुए पूरे देश के लिए मॉडल बन रही है। संयुक्त समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी को ओडीओपी का उपहार और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया।

डुमुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज कॉमन मैन और खासतौर पर अन्नदाता किसानों को स्पर्श करती तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश इन योजनाओं में अच्छा कार्य कर रहा है और प्रदेश सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश अपनी ओर से बेस्ट रिजल्ट देगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 प्रख्यापित की गई है। इसके अंतर्गत राज्य में कम लागत की विश्वसनीय सौर ऊर्जा तक आम लोगों की पहुंच को सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 और उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 भी प्रख्यापित की जा चुकी है।

डुमुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने सोलर पॉलिसी के तहत 2027 तक सोलर प्रोडक्शन में 22 हजार मेगावाट से अधिक का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत सोलर पार्कों का विकास, कृषि फीडरों और निजी ऑन ग्रिड पंपों के सोलराइजेशन को बढ़ावा देना, एक्सप्रेसवे और रेलवे ट्रैक के किनारे सौर संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देना सहित सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना है। साथ ही सौर परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है।

डुपीएम सूर्य घर योजना को लेकर मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष एक लाख से ज्यादा इंस्टॉलेशन पूर्ण कर लिए गए हैं। उन्होंने यूपीनेडा के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन लोगों ने भी योजना के अंतर्गत आवेदन किया है सभी को अभियान चलाकर शीघ्र से शीघ्र सोलर एनर्जी से जोड़ा जाए। अभी हर महीने 11 हजार से अधिक इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं, जिसे 2025-26 में बढ़ाकर औसतन 22 हजार से अधिक किया जाए। जनपदवार, डिस्कॉमवार, नगर निगम, नगर पालिका को लक्ष्य आवंटित किया जाए। इसके प्रभावी अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए सीएम डैशबोर्ड के साथ इंटीग्रेटेड किया जाए।

डुमुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि पोर्टल पर मार्च 2025 तक प्राप्त 10.73 लाख आवेदनों पर कॉलिंग कर वेंडर्स को सूची उपलब्ध कराते हुए सोलर रूफटॉप की स्थापना की जाए। आवश्यकता के अनुरूप वेंडर्स की संख्या में वृद्धि की जाए। उन्होंने बताया कि हमारा फोकस ट्रेनिंग पर भी है, ताकि अधिक से अधिक सूर्य मित्रों को इंस्टॉलेशन के लिए तैयार किया जा सके। इसके लिए पॉलीटेक्निक के माध्यम से भी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है।

डुपीएम कुसुम योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश निजी पंप सोलराइजेशन में देश में प्रथम है। निजी नलकूपों के सोलराइजेशन के लिए मिशन मोड में कार्य किया जाए। जल्द से जल्द सभी को सोलर पैनल से आच्छादित किया जाए। अच्छे वेंडर्स को इसमें शामिल किया जाए। किसानों को भी पानी की बचत के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से वनटांगिया गांवों को निशुल्क सोलर पैनल की व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त सोनभद्र, मिजार्पुर, चित्रकूट, चंदौली के ट्राइबल्स को भी सोलर व्यवस्था से आच्छादित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में सोलर पार्क विकसित किए जाएं। इसके लिए नगर निगम भूमि उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही नगरों की स्ट्रीट लाइट्स को भी सोलर पार्क से जोड़ा जाए।

डुरबी विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत गेहूं खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश गेहूं क्रय के लक्ष्य को तय समय में पूरा कर लेगा। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल तक 26,641 किसानों से 1.40 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। अभी तक गेहूं क्रय कार्य की प्रगति विगत वर्षों की तुलना में बहुत अच्छी है। इस वर्ष कृषकों के मध्य तक पहुंच बनाने के लिए रणनीति के तहत कटाई के पूर्व जनपद एवं मंडलीय स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों को गांवों में संपर्क के लिए भेजा गया, जिसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। गांव में जाकर कृषकों से संपर्क कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से अवगत कराते हुए क्रय केंद्रों पर गेहूं लाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। डुउन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहं खरीद की अनुमति प्राप्त होने के फलस्वरूप कृषकों से संपर्क करके उनके गांव/दरवाजे पर जाकर भी गेहूं क्रय कराया जा रहा है। हमारी टीम फील्ड में उतरकर सभी 826 विकास खंडों में किसानों से बातचीत कर रही है। हर मंडी में किसानों के लिए बैठने और खाने-पीने की उत्तम व्यवस्था की गई है। हमारा पूरा फोकस किसानों को कम से कम समय में धनराशि प्रदान करने पर है। इसके लिए सभी क्रय केंद्रों को छुट्टी के दिन भी खोला जा रहा है और समयसीमा भी बढ़ाई गई है, ताकि किसानों को असुविधा न हो। डुकेंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश गेहूं के प्रोक्योरमेंट, पीएम सूर्य घर समेत इन सभी संबंधित योजनाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। रिन्यूएबल और ओवरआल एनर्जी में प्रदेश सरकार का कार्य उत्कृष्ट रहा है। अयोध्या और वाराणसी में सोलर को लेकर जो कार्य हुआ है वो दूसरे राज्यों के लिए आदर्श है। इसको अभियान चलाकर और बेहतर किया जाए, ताकि पूरे देश के लिए हम इसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने कहा कि बढ़ती ऊर्जा मांग के अनुरूप उत्तर प्रदेश की तैयारी सही दिशा में है।

24 घंटे में दें खराब मौसम से क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा: सीएम योगी

जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर खुद लिया था स्थिति का जायजा, अन्नदाताओं को जल्द से जल्द मुआवजा देने का दिया था आश्वासन

- खराब मौसम और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान की भरपाई करेगी योगी सरकार
- सीएम योगी ने अधिकारियों को मौके पर जाकर सर्वे करने के दिये निर्देश
- सीएम योगी ने अधिकारियों को लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी
- लखमीपुर खीरी में भीषण आग से खाक फसल का कुछ ही घंटों में दिया गया मुआवजा

सांई मीडिया ब्यूरो

लखनऊ, 10 अप्रैलः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार देर रात से प्रदेश में खराब मौसम, तेज हवा और ओलावृष्टि से अन्नदाता किसान की फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सर्वे कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों, एसडीएम और तहसीलदारों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे कराकर संबंधित विभाग को डिटेल उपलब्ध कराने के लिए आदेशित किया है ताकि 24 घंटे में अन्नदाताओं के खाते में क्षतिपूर्ति की धनराशि को भेजा जा सके। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने अधिकारियों को क्षतिपूर्ति देने में लापरवाही न करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि 9 अप्रैल की आधी रात को अचानक मौसम खराब हो गया, जिसके बाद तेज आंधी, ओलावृष्टि के साथ कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरी। इसे देखते हुए सीएम ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। बता दें कि सर्वे पूरा होने के बाद फसलों के नकुसान का मुआवजा बीमा कंपनियों के साथ राजस्व विभाग से भी दिया जाएगा।

वहीं राहत विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किया है और लोगों से अति आवश्यक कार्य पर ही घर से निकलने की अपील की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति का मुआवजा किसानों को देने के लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, एसडीएम और तहसीलदारों को मौके पर जाकर सर्वे करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही जल्द से जल्द विभाग के पोर्टल पर सर्वे रिपोर्ट लगाने के निर्देश दिये हैं। मालूम हो कि बाढ़, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से 33 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित अन्नदाताओं को ही मुआवजा दिया जाता है। वहीं राहत विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। ऐसे में विभाग ने लोगों को घरों से बहुत जरूरत होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके।

इनको दिया गया मुआवजा

लखीमपुर खीरी की गोला तहसील के ग्राम खजुहा में भीषण अग्निकांड में प्रभावित फसलों के रकबे के आधार प्रभावित किसान कुलवीर कौर, ओपेंद्र सिंह, जशमेल सिंह को 50,000 - 50,000 रुपये , सतवंत सिंह, संदीप सिंह, जसबीर कौर को 40,000- 40,000 रुपये, बलजीत कौर को 12,150 रुपये और हरजीत सिंह को 14,550 रुपये की अनुमन्य सहायता राशि दी गई। इसी तरह मितौली तहसील के ग्राम अलियापुर व महुआढाब में बुधवार रात आए आंधी-तूफान से फसलें क्षतिग्रस्त हो गईं। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए "मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकाड दुर्घटना सहायता योजना" के तहत उप जिलाधिकारी रेनू मिश्रा और तहसीलदार भीमसेन ने किसान सुधा देवी को 0.390 हेक्टेयर फसल क्षति पर 11,700 रुपये और ब्रजराज सिंह को 0.150 हेक्टेयर नुकसान पर 4,500 रुपये की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। वहीं तहसील सदर के ग्राम खजुहा परगना पैला तहसील लखीमपुर में बुधवार रात्रि लगभग 9:50 बजे हुए अग्निकाण्ड में गन्ने की फसल की क्षति हुई। आकलन/मूल्यांकन आख्या पर एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर/प्रशासक कृषि उत्पादन मंडी समिति अमिता यादव तहसीलदार सुशील प्रताप सिंह ने सुशील कुमार को 3,220 रुपये व बाबूराम को 6,119 रुपये की आर्थिक सहायता/ क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई।

लखमीपुर खीरी में भीषण आग से खाक फसल का कुछ ही घंटों में दिया गया मुआवजा

लखमीपुर खीरी में बुधवार शाम को तहसील गोला के ग्राम खजुहा, परगना कुकरा में अचानक भीषण आग से कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही लखीमपुर खीरी जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल नुकसान का जायजा लेने प्रभावित क्षेत्र में पहुंची। यहां उन्होंने नुकसान का आकलन करने के साथ अन्नदाताओं से बातचीत की। साथ ही अन्नदाताओं को जल्द से जल्द मुआवजा देने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने मौके पर ही अधिकारियों को तत्काल नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिये और जल्द से जल्द रिपोर्ट डीएम ऑफिस में समिट करने के निर्देश दिये। डीएम ने कुछ ही घंटों में गुरुवार को आगजनी की घटनाओं से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए लखीमपुर सदर, मितौली और गोला तहसील के किसानों को फसल क्षति के एवज में सरकार द्वारा अनुमन्य धनराशि के चेक प्रदान किए। इससे अन्नदाताओं मायूस चेहरे खिल उठे।

मुरादाबाद में भी अटल आवासीय विद्यालय की बिल्डिंग बनकर तैयार, सीएम करेंगे शुभारंभ

बरेली के बाद अब मुरादाबाद मंडल में भी अटल आवासीय विद्यालय अपने खुद के भवन में होगा संचालित

शुभारंभ के साथ ही सभी 18 मंडलों में विद्यालय की अपनी खुद की बिल्डिंग में लगने लगेगी क्लास
अभी तक बरेली के बच्चे लखनऊ में तो मुरादाबाद के बच्चे बुलंदशहर में कर रहे थे अध्ययन
मुरादाबाद मंडल के 640 छात्र नए शैक्षिक सत्र में अपने विद्यालय और छात्रावास में कर सकेंगे पढ़ाई
लगभग 70 करोड़ की लागत से बनी है अत्याधुनिक सुविधाओं वाली भव्य इमारत

सांई मीडिया ब्यूरो

लखनऊ, 10 अप्रैल। निर्माण श्रमिकों के बच्चों और कोरोनाकाल में निराश्रित हुए बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालयों की शुरूआत की थी। उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण और आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इसी क्रम में बरेली के बाद अब मुरादाबाद में भी अटल आवासीय विद्यालय की शानदार इमारत बनकर तैयार हो चुकी है। एक मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस इमारत का शुभारंभ कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय अपनी-अपनी बिल्डिंग से संचालित हो सकेंगे।

बरेली और मुरादाबाद के बच्चे जो पहले लखनऊ और बुलंदशहर जैसे अन्य जिलों में पढ़ाई कर रहे थे, अब उन्हें अपने ही मंडल में सुविधायुक्त अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिलेगा। इससे न सिर्फ उन्हें बेहतर शिक्षा बल्कि सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल भी प्राप्त होगा। अटल आवासीय विद्यालयों में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (वढइडउह) में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के साथ-साथ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र अनाथ बच्चों और कोविड काल में माता-पिता को खो चुके बच्चों को भी प्राथमिकता से प्रवेश दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में इन विद्यालयों का औपचारिक उद्घाटन किया गया था, जबकि आधारशिला स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2020 को रखी थी। अब यह सपना साकार हो रहा है। मुरादाबाद में तैयार यह विद्यालय 13.5 एकड़ में फैला है और इसमें एकेडमिक ब्लॉक, रेसीडेंस ब्लॉक और छात्रावास की अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध है। कुल 1000 छात्रों के बैठने की क्षमता वाले इस विद्यालय में फिलहाल 640 छात्र-छात्राएं नए सत्र से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। इस बिल्डिंग में 28 क्लासरूम, 11 आधुनिक प्रयोगशालाएं और लाइब्रेरी, 6 ट्यूटोरियल रूम 300-300 सीनियर गर्ल्स और बॉयज डॉरमेट्री, 200-200 जूनियर गर्ल्स और बॉयज डॉरमेट्री, 6 टाइप-1, 6 टाइप-2 और 30 टाइप-3 रेजिडेंशियल फ्लैट्स, प्रिंसिपल आवास, सेपरेट मेस, एसटीपी, 1000 किलोवाट की ईएसएस (इलेक्ट्रिक सब स्टेशन) है। इस बिल्डिंग की निर्माण लागत लगभग ड्ड70 करोड़ रुपए है।

करणी सेना के संभावित कार्यक्रम को दृष्टिगत पुलिस कमिश्नरेट आगरा द्वारा दंगा नियंत्रण योजना के मॉक ड्रिल का आयोजन

आरती यादव

आगरा। दिनांक 12 अप्रैल 2025 को करणी सेना द्वारा संभावित कार्यक्रम के मद्देनजर आगरा पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्क है एवं इसी क्रम में दिनांक 10.04.2025 को पुलिस लाइन्स, आगरा स्थित परेड ग्राउण्ड में दंगा नियंत्रण योजना के मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

इस दौरान अपर पुलिस आयुक्त एवं पुलिस उपायुक्त नगर द्वारा समस्त सहायक पुलिस आयुक्त (ACP), समस्त थाना प्रभारीगण एवं भारी संख्या में तैनात पुलिस बल के साथ मॉक ड्रिल का आयोजन कर, संभावित भीड़, उग्र विरोध प्रदर्शन अथवा कानून व्यवस्था को भंग करने वाली स्थितियों से प्रभावी रूप से निपटने हेतु दंगा नियंत्रण उपकरणों जैसे– बॉडी प्रोटेक्शन किट, हेलमेट, डण्डा, केन शील्ड, टियर गैस, एण्टी रायट गन, टीयर स्मोक ग्रेनेड, वायरलेस संचार उपकरण आदि का सघन अभ्यास किया गया। एवं ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी का भी अभ्यास किया गया ताकि किसी भी अराजक स्थिति पर निगरानी रखते हुए प्रभावी कदम उठाये जा सके।

इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आगामी कार्यक्रम के दौरान शहर की शांति व्यवस्था, सौहार्द और कानून-व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान न आने पाए।आगरा पुलिस द्वारा अतिरिक्त बल की तैनाती, सीसीटीवी सर्विलांस, ड्रोन निगरानी, एवं क्यूआरटी की तैनाती की जा रही हैं। पुलिस द्वारा क्षेत्र के नागरिकों से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना के आधार पर कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। सोशल मीडिया टीम द्वारा 24/7 सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर निगरानी भी की जा रही है एवं किसी भी अराजकता वादी टिपण्णी या पोस्ट नजर रखी जा रही है।आगरा पुलिस आमजन से अपील करती है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, कानून का पालन करें और शांति बनाए रखने में सहयोग करें। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या सूचना के लिए नागरिक 112 पर संपर्क करे अथवा नजदीकी पुलिस स्टेशन से तुरन्त सम्पर्क करें।

सेवा, सुरक्षा, संवेदना झ हमारा संकल्प है और आगरा पुलिस इसका पूर्ण पालन करते हुए नागरिकों की सेवा में सदैव तत्पर है।

इमरजेंसी ट्रामा फैसिलिटिज को और मजबूत करेगा COMET-25, 500 डॉक्टर्स करेंगे प्रतिभाग

सीएम योगी की मंशा के अनुरुप प्रदेश में आपातकालीन चिकित्सा सेवा को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जा रहा कॉन्क्लेव

सांई मीडिया ब्यूरो

लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इसी का असर है कि आठ साल पहले जिस प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहा जाता है आज वह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। योगी सरकार ने अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता को बढ़ाया है और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल रूप से सुदृढ़ करने के लिए भी कई योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि अस्पतालों में ई-हेल्थ कार्ड और टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरूआत, ताकि लोगों को समय रहते चिकित्सकीय सलाह मिल सके। इसी के तहत सीएम योगी के नेतृत्व में राजधानी लखनऊ में शुक्रवार से एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम है 'COMET-2025' है। यह सम्मेलन आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा और आपदा प्रतिक्रिया के मुद्दों पर केंद्रित होगा।

कॉन्क्लेव ऑफ मेडिकल इमरजेंसी एंड ट्रामा (सीओएमईटी-25) के संचालक डॉ. लोकेंद्र गुप्ता ने बताया कि सम्मेलन 11 अप्रैल से शुरू होगा और तीन दिन तक चलेगा। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करना और विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है। इस सम्मेलन में 500 से अधिक विशेषज्ञ, शासकीय अधिकारी, मीडिया प्रतिनिधि और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य विषय 'गोल्डन आवर' रखा गया है, जो चिकित्सा आपातकालीन स्थितियों में वह महत्वपूर्ण समय है, जब त्वरित इलाज से जीवन बचाया जा सकता है। जैसे कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति, दिल का दौरा या स्ट्रोक के मरीजों को यदि समय रहते इलाज मिल जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। 'गोल्डन आवर' के दौरान दी गई चिकित्सा मदद से कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, और यह समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। सम्मेलन के पहले दिन 11 अप्रैल को केजीएमयू और राम मनोहर लोहिया में विशेषज्ञों द्वारा डॉक्टर्स को गोल्डन आवर के दौरान क्या करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा 12 और 13 अप्रैल को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विशेषज्ञ डॉक्टर्स गोल्डन आवर पर चर्चा करेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे।

डॉ. लोकेंद्र ने बताया कि योगी सरकार की विभिन्न पहलों से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो रहा है और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। सम्मेलन के जरिए प्रदेश में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही सम्मेलन में हिस्से लेने वाले डॉक्टर्स को 'गोल्डन आवर' के महत्व के बारे में बताया जाएगा ताकि समय रहते उपचार मिल सके और हर साल होने वाली हजारों मौतों को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सम्मेलन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वास्थ्य क्षेत्र में निरंतर सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उम्मीद है कि इसके परिणामस्वरूप प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय नागरी लिपि संगोष्ठी का आयोजन किया

महेंद्रगढ़: देश विदेश में नागरी लिपि का प्रचार प्रसार करने वाली प्रतिनिधि संस्था नागरी लिपि परिषद ने अपनी स्थापना के पंजीकरण की स्वर्ण जयंती पर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ में एक अंतरराष्ट्रीय नागरी लिपि संगोष्ठी का आयोजन किया । इसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय कुलपति प्रो टंकेश्वर कुमार ने की। नागरी लिपि परिषद के अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति डॉ प्रेमचंद पातंजलि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। महामंत्री डॉ हरिसिंह पाल के मार्गदर्शन में पत्रकारिता विभाग के प्राध्यापक डॉ नीरज कर्ण सिंह ने संगोष्ठी का संचालन किया। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, हिंदी भाषा विभाग, संस्कृत भाषा विभाग, राजभाषा विभाग और नागरी लिपि परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस संगोष्ठी का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन और विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत स्वस्ति वाचन से हुआ। इस अवसर पर नागरी लिपि परिषद द्वारा प्रकाशित विभिन्न भाषा प्रवेशिकाओं और नागरी संगम विशेषांकों की पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन कुलपति डॉ कुमार द्वारा किया गया। स्वागत भाषण पत्रिकारिता विभागाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार ने प्रस्तुत किया।विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति डॉ कुमार ने नागरी लिपि परिषद के अध्यक्ष डॉ प्रेमचंद पातंजलि, महामंत्री डॉ हरिसिंह पाल, कोषाध्यक्ष आचार्य ओमप्रकाश, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पूर्व उपनिदेशक डॉ भगवती प्रसाद निदारिया, हिंदी प्रेमी मंडल, हैदराबाद (तेलंगाना) के अध्यक्ष चवाकुल रामकृष्ण राव, और सिंघानिया विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष डॉ रामनिवास मानव का स्वागत विश्वविद्यालय के विशेष अंगवस्त्र और पौधा भेंट कर किया। इस अवसर पर परिषद की ओर से अध्यक्ष और महामंत्री ने कुलपति डॉ टंकेश्वर कुमार को ,परिषद के विशेष अंगवस्त्र,शाल और नागरी साहित्य भेंट कर सम्मानित किया गया । हिंदी प्रेमी मंडल, हैदराबाद के अध्यक्ष श्री चवाकुल रामकृष्ण राव की ओर से कुलपति प्रो कुमार, पत्रकारिता विभागाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ बीरपाल सिंह यादव, डॉ निदारिया, डॉ मानव,संस्कृत विभाग के प्रमुख डॉ देवेन्द्र सिंह, डॉ सुमन, राजभाषा अधिकारी डॉ कमलेश को सम्मानित किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में कुलपति डॉ कुमार ने राष्ट्रीय महत्व के इस आयोजन को उनके इस विश्वविद्यालय आयोजित करने के लिए नागरी लिपि परिषद के प्रति आभार व्यक्त किया।

' राष्ट्रीय नागरी लिपिः वैज्ञानिकता और एकात्मकता ' विषय पर आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय नागरी संगोष्ठी का विषय प्रवर्तन परिषद के महामंत्री एवं संगोष्ठी राष्ट्रीय प्रभारी डॉ हरिसिंह पाल ने किया। संगोष्ठी में डॉ रामनिवास मानव, आचार्य ओमप्रकाश,चवाकुल रामकृष्ण राव और डॉ निदारिया ने अपने शोध पत्रों का वाचन किया । उद्घाटन सत्र को धन्यवाद ज्ञापन हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ बीरपाल सिंह यादव ने किया।

द्वितीय सत्र में आस्ट्रेलिया के प्रवासी भारतीय डॉ भावना कुंअर और श्री प्रगीत कुंअर, नीदरलैंड के डॉ रामा तक्षक, चेन्नई, तमिलनाडु की डॉ राजलक्ष्मी कृष्णन, डिब्रूगढ़, असम के पत्रकार श्री ललित शर्मा, काशी विद्यापीठ के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ राजमुनि,कैडरमा झारखंड के शिक्षा प्राध्यापक डॉ अशोक अभिषेक, आथर्स गिल्ड आफ इंडिया के महासचिव डॉ शिवशंकर अवस्थी ने भाग लिया और अपने विचार प्रकट किए।

तकनीकी सत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चेन्नई के संयुक्त निदेशक (राजभाषा) डॉ श्याम सुन्दर कथूरिया ने सूचना प्रौद्योगिकी और नागरी लिपि पर अपना रोचक और विविध जानकारी से परिपूर्ण पी पी टी व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी की आधुनिक तकनीकों की सोदाहरण जानकारी दी।इस सत्र में विश्वविद्यालय की हिंदी अधिकारी डॉ कमलेश, संस्कृत विभाग की प्राध्यापक डॉ सुमन रानी ने भी विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद ज्ञापन संगोष्ठी संयोजक डॉ नीरज कर्ण सिंह ने किया। संगोष्ठी का समापन सामूहिक राष्ट्रगान के साथ किया गया।

औद्योगिक विकास में उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक छलांग

सांई मीडिया ब्यूरो

लखनऊ उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास की दिशा में नए इतिहास रच रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इन्वेस्ट यूपी 2.0 के तहत राज्य ने जिस तरह से उद्योग जगत को नीति, सुरक्षा और सुविधाओं का मजबूत आधार प्रदान किया है, उसका परिणाम अब ठोस रूप में सामने आ रहा है। भारत सरकार द्वारा संचालित वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) के ताजा आंकड़े इस परिवर्तन की सशक्त तस्वीर पेश कर रहे हैं। साथ ही इस वर्ष प्रदेश में सबसे अधिक फैक्ट्रियों का पंजीकरण हुआ है,जो कि वर्ष 2020-21 के मुकाबले लगभग दोगुना है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश में कुल 3318 नई फैक्ट्रियों का पंजीकरण हुआ है। जो कि अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि में से एक है। खास बात यह है कि इन पंजीकृत इकाइयों में से 460 फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं, जहाँ सौ से अधिक कर्मचारी कार्यरत होंगे। यह स्पष्ट संकेत है कि यूपी अब न केवल छोटे और मझोले उद्योगों को आकर्षित कर रहा है, बल्कि बड़े औद्योगिक निवेश के लिए भी अब एक प्रमुख गंतव्य बन चुका है। वर्तमान की यह उपलब्धि वर्ष 2020-21 के मुकाबले लगभग दुगुनी वृद्धि को दशार्ती है। 2020-21 में 1484 नई फैक्ट्रियों का पंजीकरण हुआ था।जिसमें बाद के वर्षों में लगातार वृद्धि हो रही है। जो कि प्रमाणित करता है कि राज्य में इज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ा सुधार हुआ है।

उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक पंजीकरण के मामले में निरंतर प्रगति करते हुए भारत सरकार के एएसआई फ्रेम में भी उल्लेखनीय बढ़त पाई है। वर्ष 2022-23 में एएसआई फ्रेम में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़कर 7.6 प्रतिशत तक पहुँच गई, जो कि प्रदेश की अब तक की सबसे ऊँची स्थिति है।औद्योगिक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) के स्तर पर भी उत्तर प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। वर्ष 2022-23 में राज्य का जीवीए बढ़कर 1.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो देश के कुल औद्योगिक जीवीए में 6.1 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित करता है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ पंजीकरण के आँकड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्पादन, मूल्य संवर्धन और रोजगार निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतिगत प्रतिबद्धता, जिसमें उद्योगों के लिए बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, तेजगति से स्वीकृति प्रक्रियाएं, सिंगल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचा और क्रियान्वयन में पारदर्शिता ने निवेशकों का विश्वास मज़बूत किया है। देश के बड़े औद्योगिक घराने ही नहीं बल्कि विदेश के निवेशक भी उत्तर प्रदेश को अब एक स्थायी और लाभकारी औद्योगिक डेस्टीनेशन के रूप में देख रहे हैं।औद्योगिक क्षेत्र की यह उपलब्धि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

***वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक 3318 नई फैक्ट्रियां हुई पंजीकृत**
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों ने खोले संभावनाओं के द्वार
इन्वेस्ट यूपी 2.0 के तहत यूपी ने उद्योग क्षेत्र में हासिल किए सफलता के नये मकाम
वर्ष 2020-21 की तुलना में लगभग दोगुना फैक्ट्रियों का हुआ है पंजीकरण
औद्योगिक निवेश का ड्रीम डेस्टीनेशन बन कर उभर रहा यूपी

गुमशुदा की तलाश

नाम : विशनु
पिता का नाम : कांति प्रसाद
कद 3,4, रंग : गोरा
गुम होने की तारीख 2-4-25
जिसने छिट
की लाल कमीज पहनी है
दिमाग से थोड़ा कमजोर है

जिन भाइयों को मिले कृपया इस नंबर पर सूचित करें
7838647280 कांति प्रसाद
9417819767 उप निरीक्षक संजीव कुमार खोड़ा
कॉलोनी थाना खोड़ा
जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश

योगी सरकार के 'दस के दम' अभियान से अपराधियों की टूटी कमर, ऑपरेशन त्रिनेत्र बना काल

सांई मीडिया ब्यूरो

लखनऊ, 10 अप्रैल:* मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति ने पिछले आठ वर्षों में अपराधियों की कमर तोड़ कर रख दी है। इस दौरान एक लाख से अधिक अपराधियों को जेल और मुठभेड़ में 227 को यमलोक भेजा गया। इतना ही नहीं योगी सरकार के निर्देश पर मिशन शक्ति फेज-5 के तहत प्रदेशभर में ह्यदस का दमह्ल नामक विशेष ऑपरेशन चलाए गए। इसमें ऑपरेशन गरुड़, ईगल, मजनू, रक्षा, बचपन, खोज, शील्ड, डेस्ट्राय, नशा मुक्ति और त्रिनेत्र आदि शामिल हैं। इन ऑपरेशन के जरिये यूपी पुलिस ने महिलाओं, बेटियों, बच्चों, युवाओं और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। वहीं ऑपरेशन त्रिनेत्र ने जघन्य अपराधों का खुलासा कर अपराधियों को सलाखों के पीछे धकेला है।

डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि सीएम योगी की मंशानुसार मिशन शक्ति फेज-5 के तहत यूपी पुलिस ने प्रदेश भर में दस ऑपरेशन चलाए। यूपी पुलिस का यह अभियान अपराधियों के लिए काल बन गया है। योगी सरकार का ह्यदस का दमह्ल ऑपरेशन ने प्रदेश को अपराध से मुक्त करने की संकल्पना है, जिसे जमीन पर सफलतापूर्वक उतारा गया है। इन ऑपरेशन के जरिए 1 लाख से अधिक लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।

डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत प्रदेश भर में संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया। इसके बाद प्रदेशभर में 11,07,782 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ये सीसीटीवी थानों से जोड़े गए ताकि कैमरा कंट्रोल रूम्स से घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी का नतीजा है कि डकैती, लूट समेत कुल 5,718 जघन्य अपराधों का सफल खुलासा किया गया।

महिलाओं और बच्चियों से जुड़े साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया। अभियान के तहत 2,597 प्राथमिकी पत्रों की जांच की गई, जिनमें से 2,407 का निस्तारण किया गया। वहीं पूर्व में पंजीकृत 1,179 अभियोग में से 449 का निस्तारण किया गया और 498 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 405 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए। इसी तरह स्कूल-कॉलेजों के आसपास बच्चों और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों सौहदों के खिलाफ ऑपरेशन मजनू चलाया गया। इस अभियान में 7,554 स्थानों को चिह्नित किया गया और 58,624 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं ऑपरेशन ईगल के तहत महिलाओं से संबंधित अपराधों में जेल से बाहर आए 7,963 अपराधियों में से गिरफ्तार-हाजिर अदालत 5,166 को चिन्हित किया गया। इसके दौरान 2,683 अभियुक्त गिरफ्तार-हाजिर अदालत हुए। वहीं 4,294 के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। ऑपरेशन रक्षा के तहत स्पा सेंटर, मसाज पार्लर में छिपे मानव तस्करी के मामलों में 56 महिलाओं/बालिकाओं को रेस्क्यू कर 49 का पुनर्वास कराया गया।

प्रदेश में बल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति समेत बच्चे के अधिकारों के लिए ऑपरेशन बचपन और खोज चलाया गया। इसमें ऑपरेशन बचपन के तहत बाल श्रम व बाल भिक्षावृत्ति के मामलों में 2,860 बच्चों को बचाया गया। वहीं 1,207 केसों में कार्यवाही हुई। इसी तरह ऑपरेशन खोज के तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आश्रयगृहों से 3,327 गुमशुदा बच्चों को पुनर्वासित किया गया।

ऑपरेशन शील्ड के तहत 29,773 एसिड की दुकानों को चेक किया। वहीं 725 के खिलाफ कार्रवाई की गयी। ऑपरेशन डेस्ट्राय के तहत अश्लील साहित्य व सीडी के 748 मामले अभियोग दर्ज हुए। ऑपरेशन नशा मुक्ति के तहत नशे के विरुद्ध 4,750 हॉट स्पॉट चिन्हित कर 2,752 अभियोग पंजीकृत किए गए और 33,391 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

संक्षिप्त समाचार

गोरखपुर डबल मर्डर: खुशबू ने पुलिस पर थप्पड़ मारने का लगाया आरोप, मां-बहन की हत्या अभी भी अनसुलझी

गोरखपुर , एजेंसी। चौरीचौरा डबल मर्डर के खुलासे के करीब पुलिस का पहुंचने का दावा है। इसी बीच बुधवार को मृतक पूनम की बेटी खुशबू ने पुलिस पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाते हुए चौरीचौरा तहसील पहुंच गई।

अपने भाई और ग्रामीणों ने साथ तहसील पहुंची खुशबू ने आरोप लगाया कि पुलिस मां और बहन के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। इसके अलावा पुलिस ने बुधवार को परिवार पर दबाव बनाने के साथ उन्हें थप्पड़ मार दिया।

दरअसल, 29 मार्च की देर रात करीब 1:30 बजे मां-बेटी पूनम (45) और उसकी बेटी अनुष्का (13) की गड़ासे से मारकर हत्या की गई थी। सूचना पर पहुंची चौरीचौरा पुलिस ने घटना स्थल पर छानबीन की थी। तब पूनम का एंड्रॉयड मोबाइल वहां नहीं मिला था। पांच दिन खेत में पूनम का मोबाइल मिला था।

वहीं, सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान पहले कमरे की दीवार के झरोखे से हत्यारोपियों के पैर देखने का दावा करने वाली मृतका की बेटी खुशबू अपने बयान से पलट गई है। वह अब कोई और कहानी पुलिस को सुना रही है।

पत्नी को पंचायत के लिए थाने लेकर पहुंचा, पति ने बेटे को ही उठाकर सड़क पर पटक दिया- गंभीर

गोरखपुर , एजेंसी। गोरखपुर एम्स इलाके के नंदानगर दरगाहिया निवासी आकाश का पत्नी से विवाद चल रहा है। बुधवार को पति पत्नी एम्स थाने में एक दूसरे की शिकायत लेकर पहुंचे थे। इस दौरान थाने के बाहर आकाश ने अपने दो साल के बेटे को उठाकर पटक दिया। गंभीर हालात में बच्चे का निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। आरोपी पिता को पुलिस ने हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ।

जोगी नवादा गोलीकांड: बरेली में मंत्री के रिश्तेदार समेत दो आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क

बरेली , एजेंसी। बरेली के जोगी नवादा गोलीकांड के आरोपियों पर कार्रवाई जारी है। भाजपा नेता के भतीजे और उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार समेत दो आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए पुलिस ने मंगलवार रात उनके घरों पर नोटिस चस्पा कर मुनादी करा दी। आरोपियों के बारे में सटीक सूचना देने वाले को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई।

क्या है मामला: पिछले साल बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा में महिला वकील रीना सिंह के पति और परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर जानलेवा हमला किया गया था। रीना के पति का अब भी इलाज चल रहा है। इस मामले में 11 लोग नामजद कराए गए थे, जो स्थानीय भाजपा नेता के भतीजे और उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार थे।

कुछ आरोपियों को पुलिस ने थोड़े दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया तो कुछ कोर्ट में हाजिर हो गए थे। लंबे समय तक चार आरोपियों का सुराग नहीं मिला। इनकी तलाश में पुलिस ने उत्तराखंड तक दबिश दी। एसएसपी अनुराग आर्य ने चारों आरोपियों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

दो आरोपी कर चुके हैं सरेंडर : हाल ही में दो इनामी आरोपियों विशाल राठौर और आकाश राठौर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जबकि अभिषेक और टिंकू राठौर का सुराग नहीं लगा। बारादरी थाना पुलिस ने अभिषेक और टिंकू राठौर की तलाश के लिए हरसंभव प्रयास किया। सफल न होने पर उनकी संपत्ति कुर्की के लिए कोर्ट में आवेदन किया था। इसी मामले में कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है। पुलिस पहले भी कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

विवेचना में खुले चार और आरोपियों के नाम: जोगी नवादा गोलीकांड में वीडियो और साक्ष्यों के आधार पर चार और आरोपियों के नाम प्रकाश में आए हैं। इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि विवेचना में रामगोपाल मिश्रा, रजत राठौर, हिमालय राठौर व अमित राठौर के नाम प्रकाश में आए हैं। पता लगा है कि ये लोग भी फायरिंग करने वालों में शामिल थे। पुलिस ने इनकी तलाश की तो ये फरार हो गए।

संघ और सरकार मिलकर तैयार करेंगे 2027 का रोडमैप

निष्क्रिय स्वयंसेवकों को फिर किया जाएगा सक्रिय

लखनऊ, एजेंसी। संघ परिवार और सरकार मिलकर विधानसभा चुनाव 2027 का रोडमैप तैयार करेंगे। इसके लिए रोजगार, रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती और किसानों-गरीबों से जुड़े मुद्दों पर खास फोकस होगा। इस संबंध में मंगलवार को संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल की मौजूदगी में संघ के आर्थिक समूह के साथ समन्वय बैठक में जनता के फीडबैक के आधार पर सरकार को काम करने का सुझाव दिया गया। निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में संघ के सभी घटक प्रमुखों और सरकार के कई मंत्रियों की मौजूदगी में बैठक हुई। इस दौरान सहकारिता समेत कई विभागों में भर्ती न होने पर चर्चा हुई। संघ ने सरकार को रोजगार की दिशा में तेजी से काम करने और सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती का सुझाव दिया। किसानों को कर्ज से निजात दिलाने और उनकी समस्याएं सुलझाने पर ध्यान देने को कहा। भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, सहकार भारती, लघु उद्योग भारती समेत कई संगठनों के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, श्रम व सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान भी मौजूद रहे।

संविदा कर्मियों का मुद्दा भी उठा: मजदूर संघ ने संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा समेत कई मुद्दे उठाए। भारतीय किसान संघ ने कहा कि किसानों के लिए पहले की तरह आगे भी कर्ज माफी पर विचार किया जाए। मंत्रियों ने समस्याओं व उनके समाधान पर चर्चा की।

निष्क्रिय स्वयंसेवकों को फिर सक्रिय करेगा संघ: लोकसभा चुनाव 2024 में स्वयंसेवकों की निष्क्रियता के असर से सचेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) उनको फिर सक्रिय करेगा। संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने मंगलवार को राजधानी पहुंचकर प्रचारकों व अन्य पदाधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने पदाधिकारियों को ऐसे स्वयंसेवकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जो अब अलग-थलग हैं।

भागवत ने कहा, निष्क्रिय स्वयंसेवकों को सक्रिय करने के लिए पदाधिकारी उनके घर जाकर उनसे संवाद करें। उन्हें कार्यक्रमों में शामिल कराएं। राजधानी पहुंचे संघ प्रमुख सबसे पहले भारती भवन गए। लखीमपुर रवाना होने से पहले उन्होंने संघ के पदाधिकारियों व प्रचारकों से मुलाकात की। कहा, पहले संगठन का काम करने वाले स्वयंसेवकों से समस्या पूछकर निस्तारण कराएं।

संघ प्रमुख ने गांवों में शाखाओं के विस्तार पर भी जोर दिया। उन्होंने संघ के स्थापना के शताब्दी वर्ष पर पूरे साल चलने वाले अभियानों व कार्यक्रमों की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा, यह संघ का शताब्दी वर्ष है। साल भर के लिए तय अभियानों को सक्रियता से चलाएं। साथ ही अवध क्षेत्र में संघ की गतिविधियों के बारे में पूछताछ की।

हर कार्यकर्ता तक पहुंचें पदाधिकारी - भागवत: डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि पदाधिकारी हर कार्यकर्ता तक पहुंचें। जनमानस में शताब्दी वर्ष के अभियानों के जरिये राष्ट्र के प्रति चेतना का माहौल बनाकर शाखाओं का विस्तार करें। गांवों में शाखाएं बढ़ाएं। शहरों में युवाओं और पेशवरों के अलग-अलग वर्गों को जोड़ें।

मुख्यमंत्री योगी से मिले प्रभु देवा सहित निर्माता डॉ. मोहन बाबू, शिष्टाचार भेंट की

लखनऊ , एजेंसी। फिल्म कन्नप्पा के निर्माता डॉ. एम मोहन बाबू और प्रभु देवा सहित फिल्म व्यवसाय से जुड़े कई लोगों ने लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। सीएम से मुलाकात करने वालों में फिल्म कन्नप्पा के निर्माता डॉ. एम मोहन बाबू, फिल्म कलाकार विष्णु मांचू, प्रभु देवा और विनय माहेश्वरी ने शिष्टाचार भेंट की।

चोरी के रुपयों से खरीदा घर: गोरखपुर के सराफा दुकान से कर्मचारी ने की 70 लाख से अधिक की चोरी- केस दर्ज

गोरखपुर , एजेंसी। राजघाट थाना क्षेत्र के एक सराफा की दुकान (रामनिवास सराफ प्रा. लि.) में धीरे-धीरे सोना चोरी करके सेल्समैन ने 50 लाख रुपये का घर खरीद लिया। कारोबारी रायगंज के रामनिवास वर्मा ने सेल्समैन नरसिंहपुर कच्चीबाग निवासी सर्वेश वर्मा पर धोखाधड़ी कर 70 लाख रुपये से अधिक का सोना चोरी करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। राजघाट पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, रामनिवास वर्मा ने सोमवार को राजघाट थाने में केस दर्ज कराया है। उन्होंने बताया है कि दुकान पर सर्वेश वर्मा वर्ष 2022 तक बतौर सेल्स मैन काम करता था। इधर, दुकान में सामान के मिलान में अंतर मिला। तब छानबीन में पता चला कि धीरे-धीरे करके सर्वेश ने सोना हड़प लिया है।

सराफा कारोबारी ने बताया कि कार्रवाई के लिए कहने सर्वेश ने 70 लाख रुपये की ज्वेलरी चोरी करना भी स्वीकार किया। सर्वेश ने बताया है कि 50 लाख रुपये में मां के नाम से एक दो मंजिला मकान नरसिंहपुर में रजिस्ट्री कराई है। 60 ग्राम सोने की ज्वेलरी भी उपलब्ध है।

उसने रुपये व ज्वेलरी वापस करने की बात कही थी। बाद में टरकाने लगा और धमकी दी कि दुकान में आग लगा दूंगा। इस संबंध में कोतवाली सीओ ओंकार दत्त तिवारी ने कहा कि सराफा कारोबारी की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।

भाजपा नेता के होटल पर छापा, 31 जुआरियों को दबोचा

17 लाख कैश...19 लग्जरी गाड़ी जब्त; पुलिस पर भी एक्शन

मेरठ , एजेंसी। एसएसपी के आदेश पर एसपी क्राइम और सीओ दौराला ने दादरी स्थित एक होटल पर छापा मारा। पुलिस ने भाजपा नेता अंकित मोतला के होटल पर छापा मारा था। जहां से 31 जुआरियों को पकड़ा है। पुलिस ने मौके से 17 लाख कैश, 19 लग्जरी गाड़ी, 40 मोबाइल बरामद किए हैं। अंकित समेत कई जुआरी भाग गए। एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया कि इंस्पेक्टर दौराला उत्तम सिंह राठौर, दादरी चौकी इंचार्ज समेत 5 सिपाही लाइन हाजिर किए गए हैं। अंकित की मां उर्मिला देवी जिला पंचायत के वार्ड 9 से सदस्य हैं।

निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे, कामकाज ठप

लखनऊ , एजेंसी। पावर कारपोरेशन के पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्काम के निजीकरण के विरोध में बुधवार प्रदेश भर से आए बिजली कर्मियों ने लखनऊ में फील्ड हॉस्टल में धरना देकर प्रदर्शन किया। यह कर्मचारी फील्ड हॉस्टल से शक्ति भवन तक रैली निकालकर पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से निजीकरण को निरस्त करने की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के मीडिया संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि इस रैली में प्रदेश भर से अभियंता और कर्मचारी लखनऊ में निजीकरण का विरोध करके उसके प्रस्ताव को निरस्त करने आए हैं। कर्मचारियों के इस प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए कई प्रदेशों से बिजली कर्मी नेता भी आए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई पर बहुत नाराजगी जताते हुए पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्काउंट को कॉर्पोरेशन की अधीन रखने की आवाज उठाई। उधर दूसरी तरफ प्रशासन ने भी

प्रदर्शनकारी बिजली कर्मियों को शक्ति भवन तक न पहुंचने के लिए जगह-जगह वेरीकटिंग करके काफी फोर्स को मुस्तैद किया है। इससे अंदेशा है की रैली निकलने के दौरान दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

कामकाज ठप : बिजली कर्मियों की रैली के चलते बुधवार को लखनऊ समेत प्रदेश के अधिकतर कार्यालय और उपकेंद्रों पर विभागीय कामकाज पूरी तरह ठप है। इसकी वजह लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर कार्यालय के अभियंता सभी रैली में शिरकत करने पहुंचे हैं।

अप्रैल के अंत तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण, परिसर में स्थापित होंगी 18 मूर्तियां

अयोध्या , एजेंसी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण कार्य अप्रैल के अंत तक पूरा हो जाएगा। रामजन्मभूमि परिसर में काम कर रही सभी क्रेन हटा दी जाएंगी। इसके बाद परकोटा के उत्तर व पूर्व दिशा में जो काम छोड़ दिया गया है, उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राम दरबार की मूर्ति अक्षय तृतीया पर मंदिर में स्थापित कर दी जाएगी। परिसर में स्थापित होने वाली सभी मूर्तियां अप्रैल के अंत तक आयोध्या पहुंच जाएंगी। जून में अच्छा मुहूर्त देखकर सभी मूर्तियों की एक साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। परिसर में कुल 18 मूर्तियां स्थापित होंगी। परिसर में बन रहे चार द्वारों के नामकरण पर विचार किया जा रहा है। इसमें भारत की आध्यात्मिक एकात्मता के दर्शन होंगे।

गाजीपुर में डीएम की बड़ी कार्रवाई: सात लेखपाल सस्पेंड

पांच संविदा कर्मी पर एफआईआर; सीडीओ के स्टेनो का तबादला

गाजीपुर , एजेंसी। गाजीपुर जनपद में आय प्रमाणपत्र जारी करने के नाम पर चल रहे खेल मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। डीएम आर्यका अखौरी ने सात लेखपालों को निलंबित, जखनियां तहसील के पांच संविदा कर्मी ऑपरेटरों पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही पांच तहसीलदारों से स्पष्टीकरण मांगा है इसके अलावा सीडीओ के स्टेनों का तबादला जमानिया के लिए कर दिया है।

इसके अलावा संबंधित पांचो तहसीलों के तहसीलदारों से प्रकरण में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जबकि सीडीओ संतोष कुमार वैश्य के स्टेनो राधेश्याम यादव का तबादला जमानिया तहसील के लिए कर दिया गया है। क्योंकि जांच में यह भी बात सामने आई कि सीडीओ के स्टेनो की बेटी पूजा की नियुक्ति आंगनबाड़ी पद पर मनिहारी ब्लॉक के

चौखड़ी में हो गई। सूची देखकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि पूजा के पति अजीत जौनपुर में सरकारी शिक्षक पद पर तैनात हैं। ग्रामीणों ने शिकायत की तो पता चला कि उन्होंने सालाना आय 42 हजार रुपये दिखाई है। हालांकि शिकायत होते ही पूजा ने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसी तरह जिले में चल रही आंगनबाड़ी भर्ती के दौरान 14 प्रमाणपत्र ऐसे मिल चुके हैं। इसमें सीडीओ के स्टेनो की बेटी से लेकर शिक्षक, जवान, पुलिस और प्रधान, कोटेदार आदि तक के नाम शामिल हैं। ऐसे में संबंधित की नियुक्ति को होल्ड कर जांच शुरू कर दी गई है।

पूर्वांचल में छाए रहेंगे बादल, पश्चिम के 17 जिलों में लू का अलर्ट

एक झटके में छह डिग्री चढ़ा पारा

लखनऊ , एजेंसी। प्रचंड गर्मी के बीच यूपी में मौसम दो रंग दिखा रहा है। कई जिलों में बादल और बारिश की संभावना है तो कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पूर्वा हवाएं चलीं और तराई के कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही रही। बुधवार के लिए मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के लगभग 17 जिलों में लू की चेतावनी जारी किया है और पूर्वी-तराई हिस्सों में बूंदाबांदी के आसार जताए हैं।

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक यूपी के पूर्वी-तराई इलाकों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती आदि में गरज-चमक संग बूंदाबांदी के संकेत हैं। कहीं-कहीं वज्रपात के भी आसार हैं।

सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले तीन से चार दिन प्रदेश के विभिन्न इलाकों में छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। वहीं तात्कालिक तौर पर पारे में 2 से 4 डिग्री की गिरावट की संभावना है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के जिलों, बुंदेलखंड और यूपी के दक्षिण पूर्वी जिलों में लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।

मंगलवार को आगरा, झांसी समेत कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। वहीं प्रयागराज, हमीरपुर, कानपुर, मुजफ्फरनगर आदि जिलों में तापमान सामान्य से अधिक रहा और लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। रात के पारे में भी बढ़ोतरी आई।

इन जिलों में है हीट वेव (लू) की चेतावनी: गाजियाबाद, हापुड, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आसपास के इलाकों में।

रात के पारे में 6.1 डिग्री की उछाल: राजधानी में

मंगलवार को तीखी धूप के साथ उमस भरी गर्मी ने परेशान किया। इसकी वजह पूर्वा हवाएं रहीं। दिन के पारे में 1.2 डिग्री की गिरावट रही, लेकिन पुरवाई चलने से उमस भरी गर्मी रही। वहीं, रात के पारे में अप्रत्याशित रूप से 6.1 डिग्री के उछाल से हवा में गर्माहट महसूस की गई।

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बुधवार को बादलों की आवाजाही रहेगी और पारे में हल्की गिरावट के आसार हैं। विक्षोभ व पुरवाई के असर से बाराबंकी में बूंदाबांदी हो सकती है। मंगलवार को दिन का तापमान 1.2 डिग्री की गिरावट के साथ 38 डिग्री दर्ज हुआ। रात के पारे में 6.1 डिग्री का उछाल आया और तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।

संपादकीय | पेट्रोल-डीजल और गैस के बढ़े दामों विपक्ष ने उठाए सवाल

इस वक्त जब अमेरिका के पारस्परिक शुल्क थोपने से वाणिज्य-व्यापार पर पड़ने वाले असर को लेकर तरह-तरह के आकलन आ रहे हैं, केंद्र सरकार ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में दो-दो रुपए और रसोई गैस पर पचास रुपए की बढ़ोतरी की गई है। विपक्ष इसे लेकर हमलावर है। उसका कहना है कि इस समय जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पिछले चार वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है, तब भी तेल की कीमत क्यों बढ़नी चाहिए।

हालांकि सरकार का कहना है कि उसने उत्पाद शुल्क जरूर बढ़ाया है, पर इसका बोझ आम उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा। यह खर्च तेल कंपनियां वहन करेंगी। इस तरह तेल की कीमतें यथावत बनी रहेंगी। मगर इसे लेकर लोगों का भरोसा इसलिए नहीं बन पा रहा है कि सरकार अपने नफे-नुकसान के मद्देनजर तेल की कीमतों में बदलाव करती रही है। उत्पाद शुल्क का मतलब है कि वह पैसा सीधे केंद्र सरकार के खजाने में जाएगा। तेल कंपनियां कब तक यह बोझ वहन कर पाएंगी, कहना मुश्किल है।

पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क को लेकर पहले से विपक्षी दल सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर सरकार इतना भारी शुल्क किस आधार पर लगाती है। इस वक्त कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत सौ रुपया प्रति लीटर से ऊपर है। डीजल सौ रुपए के आसपास है। मगर केंद्र सरकार का तर्क है कि इस वक्त जब वैश्विक आर्थिक स्थितियां डांवाडोल हैं, इससे सरकार को अपना राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी। हालांकि दस वर्ष पहले

जब उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की गई थी, तो तर्क दिया गया था कि इस पैसे से संकट के वक्त के लिए तेल भंडार जमा किया जाएगा। उसके बाद लगातार उत्पाद शुल्क बढ़ाया जाता रहा। लोकसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा जैसे चुनावों के वक्त जरूर सरकार ने उत्पाद शुल्क कुछ घटा दिए थे। मगर फिर उसने बढ़ा दिया है। सरकार इस बात से अनजान नहीं कि तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई भी बढ़ जाती है। सरकार पहले ही महंगाई से पार पाने में नाकाम साबित हो रही है, उसके बावजूद उसे इस तरह अपना खजाना भरना ज्यादा जरूरी जान पड़ा है, तो जाहिर है, वह महंगाई को लेकर बहुत चिंतित नहीं है। पहले तेल की कीमतों का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के अनुसार होता था, पर सरकार ने उस नियम को बदल दिया। राजस्व जुटाने के लिए सरकार को नए रास्ते तलाशने ही पड़ते हैं, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसे ही मदों में बार-बार बढ़ोतरी की जाए, जिसका बोझ उठाना पहले से नागरिकों को भारी पड़ रहा हो। तेल और रसोई गैस की कीमतें पहले ही लोगों की जेब पर भारी पड़ रही हैं। महंगाई से पार पाना कठिन बना हुआ है। महंगाई की तुलना में लोगों की आय में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने से केवल लोगों के निजी खर्च नहीं बढ़ते, माल ढुलाई आदि का खर्च भी बढ़ता है, जिसका असर विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ता है। बड़ी मुश्किल से विनिर्माण क्षेत्र कुछ ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है, उसमें यह नई मार उसे परेशान कर सकती है। सरकार जब तक तेल की कीमतों को लेकर कोई व्यावहारिक नीति नहीं बनाती, तब तक यह समस्या सिर उठाती रहेगी।

यौन शिक्षा समय की मांग है - इंटरनेट पर अधूरी जानकारी खतरनाक है

माता-पिता, शिक्षकों और समाज को जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

भारतीय सभ्य समाज में सेक्स शब्द को एक व्यक्तिगत शब्द माना जाता है, जिसके कारण जब शिक्षा की बात आती है तो रूढ़िवादी विचारों वाले लोग तर्क देते हैं कि यह एक ऐसी शिक्षा है जिसके लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है और बच्चे समय के साथ यह जानकारी हासिल कर लेते हैं। लेकिन वे लोग यह नहीं जानते कि वर्तमान समय में, यानि आधुनिक समय में और प्राचीन काल में, नई तकनीकों और संचार के साधनों की प्रचुरता के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। उदाहरण के लिए, जो जानकारी बच्चों को 15-17 वर्ष की आयु में मिलती थी, वह अब 8-10 वर्ष के बच्चों को भी उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए जब हम यौन शिक्षा के विषय पर चर्चा करते हैं और इसे स्कूल स्तर से शुरू करने की बात करते हैं, तो आमतौर पर लोगों को यह संकोच होता है कि 7-8 साल का बच्चा अभी बचपन में है और बचपन में ही परिवार को उसे सम्मान और नैतिक मूल्य सिखाने की बात करनी चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि आज तकनीकी युग है और बच्चे वह सब कुछ जानते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि बच्चे नहीं जानते। दरअसल, यौन शिक्षा को लेकर अभिभावकों में भी गलतफहमी है। उन्हें पुरानी फिल्मों या प्रसव से संबंधित चीजों से यौन शिक्षा मिलती है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि बच्चों को उनके आस-पास से जो शिक्षा मिलती है वह अधूरी और अविश्वसनीय होती है, जिसके कारण बच्चे किसी भी गलत जानकारी को सही मानने लगते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को स्कूल स्तर पर ही यौन शिक्षा दी जानी चाहिए।

हम देखते हैं कि जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है तो जब हम उसे शरीर के बाकी अंगों के बारे में जानकारी देते हैं तो उसे उस अंग के बारे में बताते-बताते हम सिर्फ प्राइवेट पार्ट पर ही अटक जाते हैं लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि बच्चे को इसकी पूरी जानकारी है। जब हम लड़कियों के अंगों की बात करते हैं तो उन्हें स्पष्ट रूप से लिंग या लिंग कहने की बजाय तोता, तोता, चिड़िया कहकर टाल देते हैं। जिसके कारण जो बच्चा अपने साथियों से उन भागों के नाम सीखता है, हम उसे बेवकूफ कहने लगते हैं। लड़कियों के मामले में तो उनकी स्थिति भी दयनीय है, जबकि लड़कियों को इस शिक्षा की अधिक आवश्यकता है। यह बात अब मेडिकल शिक्षा से जुड़े लोग कहने लगे हैं कि जो मासिक धर्म लड़कियों का पहले 13 साल की उम्र में होता था, वह अब 10-11 साल की उम्र में होने लगा है। जिसके कारण जब लड़कियों को अचानक ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो वे मानसिक तनाव में रहने लगती हैं। गलत तरीके से छूना, बचपन में दुर्व्यवहार, बच्चे यह समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है।

अब सवाल यह उठता है कि यौन शिक्षा के लिए क्या उम्र होनी चाहिए। बेशक इस बारे में अलग-अलग राय हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली में स्कूल स्तर के तीन चरण होते हैं और एक बच्चे का जीवन भी इन चरणों के अनुसार बदलता है।

प्राथमिक स्तरः पहला चरण 5 से 10 वर्ष की आयु तक है, अर्थात पहली कक्षा से पांचवीं तक। विशेषज्ञों का कहना है कि यौन शिक्षा तीसरी या चौथी कक्षा से ही शुरू कर देनी चाहिए, यानी 7-8 साल से, ताकि जब बच्चा मिडिल लेवल पर जाए तो उसे बुनियादी जानकारी हो और जानकारी के अभाव में उसे शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े।

मध्य स्तरः यह अवधि बच्चे के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें लड़के/लड़की के शरीर में कई प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। अगर उन बच्चों को प्राथमिक स्तर पर ही जानकारी दे दी गई होती तो उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इस अवधि के दौरान बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है।

माध्यमिक स्तरः यह वह समय है जब कोई भी लड़का या लड़की अपने यौवन में प्रवेश करता है। यह वह समय है जब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। यदि बच्चों को उपरोक्त स्तर पर शिक्षा दी जाए तो यह संभावना नहीं है कि बच्चा कोई गलत काम करेगा।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह शिक्षा स्कूल के शिक्षकों द्वारा दी जानी चाहिए या किसी विशेष नर्स या परामर्शदाता आदि द्वारा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह शिक्षा विषय विशेषज्ञों अर्थात परामर्शदाताओं द्वारा दी जानी चाहिए। सरकार को अपनी नीति में यह बात शामिल करनी चाहिए कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में दो परामर्शदाता (एक लड़का/एक लड़की) अवश्य होने चाहिए।

शिक्षकों की भूमिकाः स्कूल शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे बिना किसी शर्मिंदगी के इस विषय को संवेदनशीलता से पढ़ा सकें।

बाल सुरक्षाः जब बच्चे अपनी शारीरिक सीमाओं, अनुचित स्पर्श और सही तथा गलत के बीच के अंतर के बारे में पूरी तरह से जागरूक होते हैं, तो वे स्वयं की सर्वोत्तम सुरक्षा कर सकते हैं। बच्चों को यह भी सिखाया जाना चाहिए कि यदि कोई उनके साथ बुरा व्यवहार करता है तो वे अपने माता-पिता या शिक्षकों को कैसे बताएं।

संस्कृति और नैतिकताः कभी-कभी लोग कहते हैं कि यौन शिक्षा हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। लेकिन सच्चाई यह है कि यहां मुद्दा गलत शिक्षा का नहीं, बल्कि सही जानकारी और सुरक्षा का है। जिस तरह हम बच्चों को अग्नि सुरक्षा के बारे में सिखाते हैं, उसी तरह उन्हें जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाइयां सिखाना भी महत्वपूर्ण है - सेक्स, रिश्तों और शरीर के बारे में।

संवेदनशील भाषा की आवश्यकताः भारत में, माता-पिता और शिक्षक अक्सर बच्चों से शारीरिक मुद्दों पर बात करते समय उपनामों या अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। यह गलत है। बच्चों को शरीर के प्रत्येक अंग का सही नाम और उद्देश्य समझाया जाना चाहिए, ताकि उनका ज्ञान सटीक हो और वे भविष्य में गलत सूचना या शर्मिंदगी का शिकार न हों।

हाल की घटनाओं के आलोक में: मार्च 2025 में एक घटना सामने आई जिसमें उत्तर प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में कक्षा 10 के दो छात्रों ने अपनी एक सहपाठी के साथ बलात्कार किया। पुलिस जांच से पता चला कि इन बच्चों को यौन शिक्षा या रिश्तों के महत्व की कोई समझ नहीं थी। इन सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि आयु-उपयुक्त शिक्षा का अभाव कितना घातक साबित हो रहा है।

जब आप किसी युवा को सुरक्षित रहने तथा सेक्स और कामुकता के बारे में सिखाते हैं, तो आप उन्हें यौन रूप से सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि लड़के/लड़की को यह सीखना होगा कि समाज में कैसे रहना है, विपरीत लिंग के प्रति सम्मान और गरिमा कैसे बनाए रखना है, यह सब शिक्षा में शामिल है।

माता-पिता की भूमिका

माता-पिता अपने बच्चों से खुलकर बात करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि इन चीजों से बच्चे का ध्यान भटक जाएगा, लेकिन वास्तव में, वे जानकारी के साथ सुरक्षित हैं। माता-पिता को भी अपने लिए एक तरह की यौन शिक्षा की आवश्यकता है, ताकि वे बिना शर्म के बात कर सकें। हम जानते हैं कि आज अधिकांश युवाओं के पास इंटरनेट है, इसलिए यदि हम उन्हें चिकित्सकीय दृष्टि से सही और गलत के बारे में कोई जानकारी या कोई दिशा-निर्देश नहीं देते हैं, तो हम उन्हें इंटरनेट पर पोर्न जैसी कोई चीज खोजने का अवसर दे रहे हैं, और फिर युवा इसे यौन शिक्षा मानने लगेंगे।"

समलैंगिकता के बारे में केवल नकारात्मक जानकारी को साझा करने की अनुमति देना तथा विषमलैंगिकता के सकारात्मक पहलुओं पर जोर देना, निश्चित रूप से स्वयं को नकारात्मक रूप से चित्रित करने के लिए हानिकारक होगा। यदि कोई युवा व्यक्ति अस्वस्थ दोस्ती को पहचानना नहीं जानता, तो हम कैसे मान सकते हैं कि वह बाद में स्वस्थ रोमांटिक रिश्ते को पहचान सकेगा और पा सकेगा।

आलोचकों का दावा है कि व्यापक यौन शिक्षा बच्चों को अधिक कामुक बनाती है और यह उम्र के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। लेकिन व्यापक यौन शिक्षा के समर्थकों का कहना है कि इसमें अभिभावकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। "किशोरों के यौनिकता के बारे में निर्णय लेने में माता-पिता सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, और हम यौनिकता से संबंधित उनके मूल्यों के बारे में परिवार में चर्चा को प्रोत्साहित करते हैं।"

स्लेबॉग कहते हैं, "अंततः, सभी यौन शिक्षक चाहते हैं कि माता-पिता भी इसमें शामिल हों।" "हम माता-पिता को यह समझने में मदद करना चाहते हैं कि यह कोई डरावना विषय नहीं है और यह गणित, विज्ञान या पढ़ाई जितना ही महत्वपूर्ण है।" यौन शिक्षा को एक महत्वपूर्ण पाठ के रूप में देखने में सफल होने के लिए, हम सभी को इस प्रक्रिया में भाग लेने की आवश्यकता है। भारतीय व्यवस्था को अब यह समझना होगा कि इस संवेदनशील विषय पर खुलकर बात करना समाज की मजबूती और बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेखक

डॉ. संदीप घंड लाइफ कोच सेवानिवृत्त अधिकारी भारत सरकार।

राहुल गांधी के फ्यूचर प्लान पर टिका कांग्रेस का भविष्य

(राकेश अचल-विनायक फीचर्स)

आने वाले दिनों के लिए कांग्रेस का 'फ्यूचर प्लान'क्या है ये राहुल गाँधी के अलावा कोई नहीं जानता ,लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस का 'फ्यूचर ' राहुल गांधी के ' फ्यूचर प्लान ' पर ही टिका है। कांग्रेस 2014 से सत्ता से बाहर हैं। और अभी उसे 2029 तक सत्ता से बाहर ही रहना है । सत्तारूढ़ होने के लिए उसे अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर ऐसा फ्यूचर प्लान ' बनाना होगा जो उसकी सत्ता में वापसी करा सके। कांग्रेस की जैसी तैयारी अभी दिखाई देती है उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस के लिए सत्ता अभी भी 'आकाश-कुसम' जैसी ही है।

पिछले दिनों गुजरात में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक और अधिवेशन में पार्टी की भावी रणनीति पर मंथन किया गया। सबकी नजर इसी मंथन से निकलने वाले उत्पाद पर टिकी रही। इस मंथन से कांग्रेस को अमृत मिला या विष ये कहना कठिन है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी के लगातार कमजोर होने के मुद्दे पर बैठक में मंथन हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह बात भी उठी कि पार्टी बीते कल की यानि अतीत की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पास फ्यूचर एक्शन प्लान नहीं है। पार्टी के एकछत्र नेता राहुल गांधी ने इस सवाल का जवाब दे दिया। राहुल गांधी ने साफ-साफ कहा कि उनके पास 'फ्यूचर एक्शन प्लान' है।

गुजरात के अहमदाबाद में 8 और 9 अप्रैल को सम्पन्न कांग्रेस के अधिवेशन का मकसद संगठन को मजबूत करना और देश के प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करना था। अधिवेशन के बाद छनकर बाहर आयी खबरों के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और महिलाओं का फिर से समर्थन हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। सूत्रों ने बताया कि राहुल ने कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में इस बात पर जोर दिया कि पार्टी के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का समर्थन है, लेकिन ओबीसी वर्गों तथा अन्य कमजोर तबकों का समर्थन भी हासिल करने की जरूरत है । राहुल ने कहा कि महिलाओं का भी समर्थन हासिल करना होगा जो देश की आबादी का करीब 50 फीसदी हैं।

कांग्रेस के इस अधिवेशन में जातीय

जनगणना और ईवीएम से फर्जी चुनाव करने से लेकर अमरीकी टैरिफ का मुद्दा भी जेरे बहस रहा। अधिवेशन में शशि थरूर जैसे नेताओं का नाम लिए बिना पार्टी में भाजपा के स्लीपर सेलों की भी बात उठी लेकिन सवाल ये है कि तमाम मुद्दों को चिन्हित करने के बाद ऐसी क्या कार्ययोजना बनाई गयी है जो भाजपा के वेग से आगे बढ़ रहे रथ को रोक सके। भाजपा पिछले एक दशक में कांग्रेस से इतना ज्यादा आगे निकल गयी है कि उसे सत्ताच्युत करना आसान नहीं है। देश जानना चाहता है कि कांग्रेस भाजपा का मुकाबला आखिर किस तरह करने जा रही है।

इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि तीव्र गति से आगे बढ़ती भाजपा को केवल और केवल कांग्रेस ही रोक सकती है,लेकिन वो भी अकेले नही। भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के सहारे ही आगे बढ़ना होगा ,लेकिन क्या कांग्रेस आने वाले दिनों में भाजपा के सहयोगियों को उससे दूर कर सकती है ? शायद नहीं ,क्योंकि हाल ही में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर तमाम लानत-मलानत के बावजूद टीडीपी और जेडीयू ने भाजपा का साथ नहीं छोड़ा है। कांग्रेस ने 2024 के आम चुनाव में अपने सहयोगी दलों के साथ भाजपा की बढ़त को कम किया ,भाजपा को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं करने दिया,किन्तु कांग्रेस भाजपा को सत्ता से अलग नहीं कर पायी।

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी कार्यकर्ताओं को हताश होने से बचाने की है। कांग्रेस का हताश कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं और आरएसएस के स्वयं सेवकों का मुकाबला नहीं कर सकता। एक दशक तक सत्ता में रहने के बाद भाजपा के कार्यकर्ता और संघ के स्वयंसेवक आर्थिक रूप से भी सम्पन्न हुए हैं। भाजपा और संघ ने इसी एक दशक में पूरे देश में संघ और भाजपा के पांच सितारा कार्यालयों की श्रृंखला खड़ी कर ली है। इलेक्टोरल बांड का अकूत पैसा भी भाजपा के पास है। ऐसे में एक मात्र रास्ता ये बचता है कि कांग्रेस एक नई आक्रमकता के साथ चुनाव मैदान में उतरे।

कांग्रेस के अधिवेशन में अच्छी बात ये रही कि स्लीपर सेल समझे जाने वाले नेताओं को भी बोलने दिया गय। असंतुष्ट नेताओं का प्रतिनिधित्व शशि थरूर जैसे नेताओं ने किया। अब कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं की संख्या पहले के मुकाबले कुछ कम हुई है। कांग्रेस अब राहुल गाँधी के नियंत्रण वाली कांग्रेस है । कांग्रेस को परिवारवाद से मुक्त करना - कराना एक अलग मुद्दा है जो शायद इस अधिवेशन में बहस के लिए नहीं आया। आ भी नहीं सकता था । यही परिवारवाद कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है और सबसे बड़ी ताकत भी। कांग्रेस के लिए ये अंतिम अवसर है ,2029 के बाद कांग्रेस मुमकिन है कि किसी कालपात्र में पड़ी दिखाई दे, वामपंथी दलों की तरह या समाजवादी दलों की तरह। राहुल गाँधी जिस दिन अपना फ्यूचर प्लान सार्वजनिक करेंगे उस दिन हम भी बता सकेंगे कि कांग्रेस का फ्यूचर क्या है ? कांग्रेस ने टाइगर मोदी जी की मांद में घुसकर उन्हें चुनौती दी है ,देखिए आगे-आगे होता है क्या ?(विनायक फीचर्स)

टैरिफ वार - ट्रंप ने चीन पर 104 पर्सेंट टैरिफ ठोका- चीन ने यूएस से लड़ाई में भारत से मदद मांगी

दुनियाँ भर की अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची - टैरिफ वार तमाम देशों के लिए मुसीबत बनाँ

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के हर देश को ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने से किसी न किसी रूप में चाहे वह आर्थिक, अवैध नागरिकता समस्या, टैरिफ, अमेरिकी फर्स्ट इत्यादि अनेकों एक्शन से दुनियाँ में तहलका मचा हुआ है। अभी 7 अप्रैल 2025 कोई हमने दुनियाँ के शेयर बाजारों को लहुलुहान होते हुए देखें। दुनियाँ भर की इकोनॉमीज में बवाल मचा हुआ है। ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा को आश्चर्यजनक रूप से कुछ महीनो की छूटदेकर दुनियाँ को तो बहुत चौंका दिया परंतु चीन से टैरिफ वॉर छेड़ा है, वहीं 2 अप्रैल में वह भारत के खिलाफ भी टैरिफ लगा चुके हैं। इस बीच अमेरिका में आने वाले महीनों में मंदी की आशंका गहराती जा रही है। अगर इन दोनों का पेच ज्यादा गहराता है तो भारत के सबसे ज्यादा बढ़ने वाला बिजनेस पर गंभीर नकारात्मक असर पढ़ सकता है। परंतु मेरा मानना है कि इन सब एक्शन से हालांकि अनेकों देशों पर नेगेटिव असर होगा,तो अमेरिका भीइससे अछूता नहीं रहेगा क्योंकि वहां भी मंदी के बादल छाए हुए हैं। अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने से एक बड़ा वर्ग बाधित होगा। अन्य देशों से आने वाली वस्तुओं पर टैक्स बोझ बढ़ने से महंगी हो जाएगी, जबकि घरेलू वस्तुएं ऑलरेडी ही महंगी है, तो सबसे पहले उसका उपयोग या उपभोग होगा, जिसका असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर जरुर पड़ेगा जो रेखांकित करने वाली बात है। दूसरी और हमनें देखें कि 7 अप्रैल 2025 को पूरे विश्व के शेयर बाजार लहुलुहान हुए, पर चीन ने रणनीतिक रूप से सरकारी कंपनियों बैंकों के माध्यम से शेयर मार्केट पर इतना असर नहीं पड़ने देने में कामयाब हुआ। आज यह मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं, क्योंकि सोमवार को अमेरिकी विभाग द्वारा पुष्टि की यह 104 पर्सेंट टैरिफ मंगलवार (8 अप्रैल 2025) की आधी रात से लागू हो गया है इसके जवाब में उधर चीन ने भी 34 पेर्सेंट टैरिफ बढ़ाकर अब 84 पेर्सेंट कर दिया है जो 10 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया है। भारत में खासकर आईटी क्षेत्र में इसका अधिक असर पड़ेगा, हालांकि अन्य क्षेत्रों में भी असर पड़ने की पूरी संभावना है, इसलिए भारत को चाहिए कि एक रणनीतिक

व्यवस्था के तहत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की आवश्यकता है।भारत को अमेरिका से राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने, अच्छे व्यापारिक संबंध बनाए रखनें, विवादों से बचने, विजन 2047 को रेखांकित कर सटीक निर्णय लेने की आवश्यकता है।इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,टैरिफ वार - ट्रंप ने चीन पर 104 पर्सेंट टैरिफ ठोका- चीन ने यूएस से लड़ाई में भारत से मदद मांगी। दुनियाँ भर की अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची - टैरिफ वार तमाम देशों के लिए मुसीबत बनाँ।

साथियों बात अगर हम दुनियाँ भर में ट्रेडवार बढ़ने की आशंका की करें तो, अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन से आयातित सामानों पर 104 पर्सेंट टैरिफ लगाकर अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। यह कदम चीन के 34 पर्सेंट जवाबी टैरिफ के बाद आया है,जिसे ट्रंप ने 'अनुचित व्यापार प्रथाओं' का जवाब बताया इस टैरिफ से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ बढ़ सकता है, कंपनियां संकट में आ सकती हैं, और वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ सकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को बड़ा झटका देते हुए 104 पर्सेंट अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है, यह टैरिफ मंगलवार आधी रात से प्रभावी हो गया है। जिसके बाद यूएस चाइना ट्रेड वॉर बढ़ गया है। 2 अप्रैल को अमेरिकी प्रेसिडेंट द्वारा टैरिफ की घोषणा करने के बाद चीन ने भी जवाबी 34 पर्सेंट का टैरिफ लगाया था। इसके बाद ट्रंप ने चीन को धमकी दी थी कि वह यदि इस जवाबी टैरिफ को वापस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। अब ट्रंप प्रशासन ने वैसा ही किया है जैसी उन्होंने धमकी दी थी। बढ़ गई है ट्रेड वॉर की आशंका, अमेरिका- चीन के बीच चल रहे इस टैरिफ युद्ध के कारण दुनियाँ में ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई है। चीन के द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि वह अमेरिका के सामने नहीं झुकेगे। ट्रंप प्रशासन के द्वारा लगाए गए इस भारी टैरिफ के बाद चीन भी बड़ा ऐलान कर दिया है। मीडिया न्यूज के अनुसार, कई रिपोर्टों में कहा गया है कि व्हाइट हाउस ने चीन पर 104 पर्सेंट अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जो आधी रात से प्रभावित हो गया है, क्योंकि चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपना 34 पर्सेंट प्रतिशोधात्मक टैरिफ वापस नहीं लिया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने एक पोस्ट में चीन की आलोचना करते हुए कहा कि बीजिंग ने गलत काम किया, वे घबरा गए, ऐसा कुछ जो वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि चीन ने टैरिफ पर बातचीत करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय वह घबराहट में काम कर रहा है।50 पर्सेंट अतिरिक्त टैरिफ लगाने की दी थी धमकी, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर अतिरिक्त 50 पर्सेंट की टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। फरवरी महीने में ट्रंप प्रशासन ने 20 पर्सेंट का टैरिफ चीन पर थोपा था।उसके बाद 2 अप्रैल को 34 पर्सेंट का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया। अब फिर से 50 पर्सेंट का नया टैरिफ लगाया है। बता दें कि साल 2018 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी अमेरिका

और चीन के बीच टैरिफ की जंग शुरू हुई थी, जिसका मकसद चीन पर दबावडालकर उसकी व्यापार नीतियों में बदलाव लाना था। अब 2025 में ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद यह टकराव फिर से तेज हो गया है, इसके साथ ही दुनियाँ में ट्रेड वॉर की आशंका भी बढ़ गई है।

साथियों बात अगर हम चीन ने यूएस से लड़ाई में भारत से मदद की अपील की करें तो, भारत में चीन की एंबेसी के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि वैश्विक व्यापार और विकास के लिए सभी देशों को बहुपक्षीयता का समर्थन करना चाहिए और एकतरफा फैसलों और संरक्षणवाद का विरोध करना चाहिए। उनके अनुसार, इस तरह के टैरिफ युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। जहां चीन अमेरिका से सीधा टकराव ले रहा है, वहीं भारत फिलहाल टैरिफ का जवाब टैरिफ से देने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत चल रही है, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है।चीन ने इस संकट के बीच भारत की ओर उम्मीद से देखा है, भारत में चीन की एंबेसी की प्रवक्ता ने कहा कि चीन और भारत दोनों विकासशील राष्ट्र हैं और ऐसे में अमेरिका के टैरिफ जैसे कदम ह्यवैश्विक दक्षिणह्ल देशों के विकास के अधिकार को छीनने की कोशिश हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन को एकजुट होकर इन चुनौतियों का मुकाबला करना चाहिए।आगे यह भी कहा कि वैश्विक व्यापार और विकास के लिए सभी देशों को बहुपक्षीयता का समर्थन करना चाहिए और एकतरफा फैसलों और संरक्षणवाद का विरोध करना चाहिए। उनके अनुसार, इस तरह के टैरिफ युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि टैरिफ वार - ट्रंप ने चीन पर 104 पर्सेंट टैरिफ ठोका- चीन ने यूएस से लड़ाई में भारत से मदद मांगी।दुनियाँ भर की अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची - टैरिफ वार तमाम देशों के लिए मुसीबत बनाँ। चीन अमेरिका से सीधा टकराव के मूड में है, तो भारत टैरिफ का जवाब टैरिफ से देने के पक्ष में नहीं जोविपक्षीय व्यापार समझौते में कारगर सिद्ध होगा।

गर्मियों में त्वचा सम्बन्धी समस्याओं को खत्म करता है नमक

गर्मियों के मौसम में महिलाओं को कई तरह की त्वचा सम्बन्धी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गर्मी में पीसने और धूप के कारण त्वचा काफी टैन और बेजान हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि आप इस मौसम में अपनी स्किन का खास ख्याल रखें। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए नमक के कुछ घरेलू घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी त्वचा को इस मौसम में सुरक्षित रख सकती हैं।

कहा जाता है कि ज्यादा नमक के सेवन से त्वचा रोग होते हैं। खुजली होने के कई कारणों में नमक भी एक कारण है। शरीर में जलन, खराश, त्वचा पर लाल चकते नमक की अधिकता से होते हैं। अगर आपके बाल जरूरत से ज्यादा झड़ रहे हैं तो सोडियम की अधिकता होना इसका एक कारण है। यह सोडियम ज्यादा नमक के सेवन से बनता है जो ज्यादा बन जाए तो बालों की जड़ों को कमजोर कर डालता है। ज्यादा नमक का सेवन करने से होने वाली इन समस्याओं के बावजूद नमक त्वचा को सुरक्षित रखता है, कैसे आइए डालते हैं एक नजर-

टोनर की तरह करें नमक का इस्तेमाल

ऑयली त्वचा से छुटकारा पाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। नमक को टोनर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए इसे एक स्प्रे बोतल में हल्का गुनगुना पानी और नमक अच्छे से मिलाएं। आप रूई का इस्तेमाल कर मिश्रण को चेहरे पर लगा सकते हैं।

नमक मिले पानी से नहाएँ

ड्राई स्किन से परेशान लोग नहाने के पानी में नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक कप पानी में आधा कप नमक डालें और इसे अच्छी तरह से मिलाएं। आप चाहे तो बाथटब को नमक डालकर पानी से भी भर सकते हैं और 15 मिनट तक बैठ सकते हैं।

स्क्रब की तरह करें नमक का इस्तेमाल

अपनी धूप से आपकी स्किन टैन हो गई है तो इसके लिए एक चम्मच नारियल तेल और नमक मिलाएं। इससे बॉडी पर स्क्रब करें।

नमक से बनाएं फेस मास्क

नमक का फेस मास्क बनाने के लिए तीन चम्मच शहद और एक चम्मच नमक मिलाएं। इस पेस्ट को अच्छे से मिलाएं और चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट बाद चेहरे को साफ कर दें।

क्या आप भी हाइपरथायरायडिज्म की समस्या से जूझ रहे हैं

आज के समय में हाइपरथायरायडिज्म की समस्या से बहुत से लोग पीड़ित होते हैं। इस स्थिति में थायरॉयड ग्रंथि आवश्यकता से अधिक थायरॉयड हार्मोन का उत्पादन करने लगती है।

आज के समय में हाइपरथायरायडिज्म की समस्या से बहुत से लोग पीड़ित होते हैं। इस स्थिति में थायरॉयड ग्रंथि आवश्यकता से अधिक थायरॉयड हार्मोन का उत्पादन करने लगती है। जिसकी वजह से शरीर में कई तरह की दिक्कते होने लगती हैं, जैसे अनिद्रा, हार्ट रेट का फ्लकचुएट होना, कमजोरी महसूस होना, वजन घट जाना, कंपकंपी होना, दस्त और थायराइड का बढ़ना आदि। लेकिन आज के समय में ऐसी किसी भी स्थिति में घबराने की बात नहीं होती। क्योंकि ऐसी ढेरों दवा या खाद्य सामग्री होती हैं, जो थायराइड से संबंधित समस्या और उसके लक्षणों को कम कर सकती है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी अक्सर कहा करते थे, कि अच्छा खाना ही आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी देता है और बचाकर भी रखता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर थायरॉयडिज्म की स्थिति से जूझने वाले लोगों के लिए क्या खाना सही है और क्या खाना गलत।

न्यूट्रिएंट रिच फूड खाएं

इस स्थिति से निपटने के लिए आपको ऐसी खाद्य सामग्री का सेवन भी करना होगा। जिनके अंदर कई तरह के विटामिन-मिनरल्स और खनिज पदार्थ शामिल हों। इसके लिए आप मशरूम, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, एवोकाडो, आदि का सेवन कर सकते हैं। इन खाद्य सामग्रियों के अंदर मौजूद कैल्शियम, जिंक, आयरन जैसे तत्व आपको सूजन से भी बचाते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बेहतर करते हैं। यही नहीं इन खाद्य सामग्रियों के जरिए हड्डियां भी तंदुरुस्त रहती हैं।

हरी पत्तेदार सब्जियां

अगर आज किसी भी बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे कि सेहतमंद रहने के लिए कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा फायदेमंद है। यही नहीं बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद भी हरी पत्तेदार सब्जी की ही पैरवी करते हुए दिखाई देंगे। पर अगर आपको थायराइड से जुड़ी कोई समस्या है तो आपके लिए हरी पत्तेदार सब्जियों में भी वह अधिक फायदेमंद होंगी, जो ब्रैसिसेकी के परिवार से आती है, जैसे ब्रोकोली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, बोक चोय, काले, फूलगोभी, शलजम आदि। आपको बता दें कि यही सब्जियां है जो आयोडीन का उपयोग शरीर में सुचारू ढंग से चला सकती हैं।

करें इन मसालों का सेवन

भारतीय रसोई के भीतर सदियों से ढेरों मसालों को उपयोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वहीं आयुर्वेद के नजरिए से शामिल किए जाने वाले यह मसाले पोषक तत्वों का खजाना होते हैं, जो कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। वहीं ऐसा ही कुछ अब विज्ञान भी मानने लगा है। अगर आपको थायराइड से जुड़ी दिक्कतों से पार पाना है तो आप अदरक, हल्दी, काली मिर्च, लौंग और मिंट का सेवन कर सकते हैं। इन मसालों के अंदर कई एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आपकी थायराइड की समस्या और उसके लक्षणों को कम कर सकते हैं।

क्या ना खाएं

ऐसा कहा जाता है जिस तरह एक सही डाइट आपकी समस्याओं को हर लेती है। उसी तरह कुछ गलत चीजें आपकी छोटी मोटी दिक्कतों को बड़ी समस्याओं में तब्दील कर देती हैं। इसलिए जितना जरूरी यह है कि आपको क्या खाना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में जो आपको थायराइड की समस्या के दौरान बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए।

आयोडीन युक्त पदार्थ

अगर आप थायराइड से संबंधित समस्या से लड़ रहे हैं तो ऐसे में जरूरी है कि आप आयोडीन युक्त खाद्य सामग्री का सेवन कम से कम करें या बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर आप आयोडीन युक्त पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे ग्रेव्स डिजीज नाम की एक ऑटो इम्यून स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए आयोडीन युक्त पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे दूध, पनीर, एग योल्क और मक्खन आदि।

ग्लूटेन युक्त सामग्री

थायराइड की समस्या से परेशान व्यक्ति को ग्लूटेन युक्त खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल इसकी वजह से शरीर में रोगी को सूजन और एलर्जी की समस्या हो सकती है। आमतौर पर घरों के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला गेहूं माल्ट और खमीर के अंदर ग्लूटे होता है। इसलिए इस तरह के पदार्थों से दूरी बनाकर रखें।

सोया

सोया उत्पाद का सेवन भी थायराइड की स्थिति में नहीं करना चाहिए। हालांकि इसके अंदर आयोडीन नहीं होता लेकिन हाल ही में टोफू को लेकर कई अध्ययन हो चुके हैं। यह अध्ययन बताते हैं कि सोया थायराइड की स्थिति को बिगाड़ सकता है। इसलिए इसके सेवन से पूरी तरह बचें।

कैफीनयुक्त पेय पदार्थ

आमतौर पर घरों या दफ्तरों में लोग चाय, कॉफी या चॉकलेट का सेवन करते हैं, जिनमें कैफीन होता है। इनके सेवन से घबराहट, चिड़चिड़ापन, और हार्ट रेट बढ़ सकता है। जो हाइपरथायरायडिज्म की स्थिति के लक्षणों को बढ़ाने का कार्य कर सकता है। अगर आपको यह समस्या है और आप सुबह की शुरुआत में ही चाय या कॉफी का सेवन करते हैं तो आप इसकी जगह हर्बल चाय, पानी या सेब के सिरके का पानी में मिलाकर सेवन कर सकते हैं।

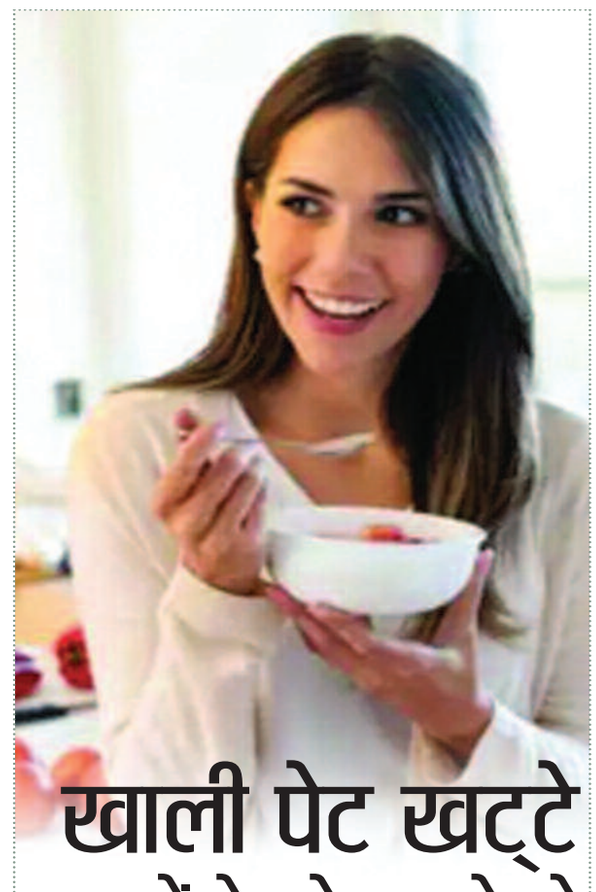

खाली पेट खट्टे फलों के सेवन से हो सकते हैं नुकसान

सुबह का नाश्ता हम सभी के लिए जरूरी है और ब्रेकफास्ट में हम सभी का खान-पान अलग वैरराइटी का होता है। जैसे किसी को सुबह के नाश्ते में पोहा और उपमा खाना पसंद है तो कोई भीगे चने या फिर फलों का सेवन करता है। नाश्ते की तस्वीरों में संतरे का रस, क्रोइसैन और ब्रेड दिखने में बहुत आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसी चीजें सुबह खाली पेट खाने से हमारी सेहत को लाभ मिलते हैं? चूंकि खट्टे फलों में एसिड पाया जाता है, जो हमारे एंगर यानी गुस्से का कारण हो सकता है। इसी तरह, खमीर युक्त ब्रेड भी पेट की सेहत को प्रभावित कर सकती है, जो भविष्य में गैस्ट्रिक की समस्या का कारण बन सकती है। इसलिए यहां हम कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं जिनके खाली पेट सेवन करने से आपको कई स्वस्थ्य लाभ मिलते हैं।

पपीता

मल त्याग को कंट्रोल करने के लिए पपीता का सेवन सही विकल्प है। खाली पेट खाने के लिए पपीपा एक सुपरफूड है। सबसे दिलचस्प बात ये है कि पपीता 12 माह यानी पूरे साल बाजार में मिलता है, इसलिए आप हमेशा के लिए इसे अपने सुबह के नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। ये फल न केवल शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर करने में मदद करता है बल्कि खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता और दिल की बीमारियों के जोखिम से बचाव करता है।

तरबूज

सुबह के नाश्ते में खट्टे फलों को छोड़ आप एप्पल जैसे दूसरे फलों को शामिल कर सकते हैं और तरबूज इस सूची में सबसे ऊपर है। 90% पानी से बना यह फल शरीर को हाइड्रेशन की एक बड़ी खुराक प्रदान करता है। यह न केवल शुगर क्रेविंग को रोकता है बल्कि इसे खाने से हम अतिरिक्त कैलोरी भी नहीं लेते। तरबूज इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है और इसमें अधिक मात्रा में लाइकोपीन यौगिक भी होता है जो हृदय व आंखों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है।

नट्स

हेल्दी गट यानी स्वस्थ्य आंत के लिए नाश्ते में मुट्ठी भर नट्स खाना बहुत जरूरी है। यह न केवल पाचन में सुधार करते हैं बल्कि आपके पेट के पीएच लेवल को भी सामान्य करते हैं। आप अपनी डेली डाइट में किशमिश, बादाम और पिस्ता को शामिल कर सकते हैं। हालांकि, आपको इन्हें कम मात्रा में ही खाएं, क्योंकि इसकी अधिक खाने से पिंपल्स और वजन बढ़ सकता है।

पोरिज

यदि आप कम कैलोरी और अधिक मात्रा के पोषक तत्वों वाला नाश्ता खाना पसंद करते हैं तो पोरिज एक बढ़िया विकल्प है। खासकर दलिया से बना पोरिज सुबह के नाश्ते का सुपरफूड है, जो स्वाद में भी लाजवाब है और सेहत के लिए हेल्दी भी है। खाली पेट पोजिर खाने से भी शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और आंतों की सेहत भी हेल्दी रहती है। दलिया खाने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है जिससे आप अतिरिक्त खाने से भी बचते हैं।

छावा, सिकंदर के बाद द गर्लफ्रेंड पर बोलीं रश्मिका

रश्मिका मंदाना की पिछली तीन फिल्मों ने 500 करोड़ से अधिक की कमाई की। आगे वह सिकंदर और द गर्लफ्रेंड में भी दिखेंगी।

अपने किरदारों से संतुष्ट हैं या अभी और कुछ पाने की इच्छा बाकी है?

मैं कभी संतुष्ट नहीं होती। मुझे लगता है कि यह हम एक्टर्स के लिए सामान्य बात है, क्योंकि हम जो भी हासिल करते हैं, उससे आगे और बेहतर करने की चाह हमेशा रहती है। जैसे मैंने पुष्पा की और अब मैं सोचती हूं कि इससे बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकती हूं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद अपनी कॉम्पिटिटर हूं। मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझसे तुलना करे या कहे कि किसी और ने मुझसे बेहतर किया।

करियर के शुरुआती दिनों के संघर्ष के बारे में बताएंगी?

ओह, वो वक्त... सच कहूं तो बहुत दर्दनाक था। ऐसा लगता था जैसे मैं पूरी ताकत से दौड़ रही हूं लेकिन मंजिल कहीं दिख ही नहीं रही। हर दिन ऐसा महसूस होता था कि बस अब और नहीं कर सकती। एक तरफ डबल शिफ्ट्स और दूसरी तरफ डायलॉग कोचिंग। कभी-कभी समझ ही नहीं आता था कि मैं यह सब क्यों कर रही हूं। उस दौर में बस एक ही बात मुझे आगे बढ़ाती थी कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। आज सोचती हूं कि वो संघर्ष नहीं होता, तो शायद मैं यहां नहीं होती। अब जब तारीफ होती है तो लगता है कि इतनी मेहनत बेकार नहीं गई।

छावा के किरदार में ढलने के लिए क्या रिसर्च की थी?

छावा के लिए मेरी तैयारी किसी महारानी की तरह ही शाही रही थी। लक्ष्मण उतेकर सर से कहा, जो आप कहेंगे, मैं करूंगी। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती लैंग्वेज थी। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है लेकिन ऑडियंस के लिए इसे सीखना मेरा फर्ज था। संवादों के लिए मैंने हर दिन 3-4 घंटे मेहनत की। यह सिलसिला पांच महीनों तक चला। मेरे लिए यह सिर्फ किरदार निभाने की बात नहीं थी, बल्कि उस किरदार की आत्मा को जीने की कोशिश थी।

वर्ग पहेली 8096

1	2	3		■	4	5	
6			■	7			■
	■	8				■	9
10	11	■	■	12		13	
■	14	15	16	■	■	17	
■	18			■	19		
20		■	■	■	21		
22		■	23			■	■

संकेत: बाएं से दाएं

1. नवंबर 1860 को अब्राहम लिंकन इस देश के सालहवें राष्ट्रपति चुने गए (4)
4. औलाद, कुलधर, वंशधर (3)
6. मध्यप्रदेश के इस अंचल में बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थित है (3)
7. बजाने वाला, कृपा करने वाला (3)
8. यह मुगलशासक अकबर के बेटे थे जिनका जन्म 31 अगस्त 1569 को हुआ था (4)
10. काला, अश्वेत, कजरारा, श्यामल (2)
12. अनेकाका, विविध, बहुरूप (4)
14. मगध देश या दक्षिण बिहार का प्राचीन वैदिक नाम, घोड़ा (3)
17. कच्चे आम या इमलीसे बनाया गया खट्ठा-मीठा पदार्थ (2)
18. धतूरा, स्वर्ण (3)
19. राजा, सम्राट, बादशाह (3)
20. स्वरूप, व्यक्तित्व, घटित (2)
21. गहन चिंतन करने का भाव (3)
22. प्रतिष्ठा, इज्जत, आबरू (2)
23. अवाम, पब्लिक, जनसमुदाय (3)

(ऊपर से नीचे

1. कृष्णपक्ष की अंतिम तिथि (4)
2. सादृश्य, मिलन, सामंजस्य, एकता (2)
3. रस्म, रीति, प्रथा (3)
4. श्रृंगार कर्म करना, संवर्धन (4)
5. शिरोमणि, मुकुट, शिखा (2)
7. नग, मणि, रत्न (3)
9. स्वजन भावना, अपनत्वपूर्णता (5)
11. वास्तव में, वाकई, सचमुच (5)
13. असुंदर, अनाकर्षक, सौंदर्यहीन (4)
15. कण का अपभ्रंश (2)
16. लगातार देखने की क्रिया, टकटकी (2)
19. माता का वह लाड़-प्यार जो उसकी संतान पर होता है (3)
20. एक प्रकार का परिधान, अंगरखा, वस्त्र, वेश (2)

वर्ग पहेली 8095 का हल

स	द्दा	म	हु	सै	न	■	प
ह	■	ह	त	■	म	शा	ल
न	म	क	■	■	क	प	ट
शी	त	■	गु	ना	ह	■	ना
ल	ल	क	ना	■	रा	जा	■
■	बी	■	■	सा	म	वे	द
■	दो	प	ह	र	■	द	■
ह	स्त	■	म	ना	ना	■	लू

सुडोकू पहेली क्रमांक- 8096

5		3						
2			3					
	4		7	1		2		3
		5	4				7	1
		4	2		1	8		
6	8				7	5		
1		7		6	9		3	
					4			6
						9		5

नियम : प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक अंक भरे जाने आवश्यक हैं, इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी व खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में अंक की पुनरावृत्ति न हो, पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।

सुडोकू पहेली क्र. 8095

2	9	3	1	7	4	8	6	5
5	1	8	6	2	3	4	7	9
6	7	4	9	8	5	2	3	1
3	8	5	2	9	6	1	4	7
1	6	9	8	4	7	5	2	3
7	4	2	5	3	1	9	8	6
4	5	1	7	6	8	3	9	2
8	2	6	3	5	9	7	1	4
9	3	7	4	1	2	6	5	8

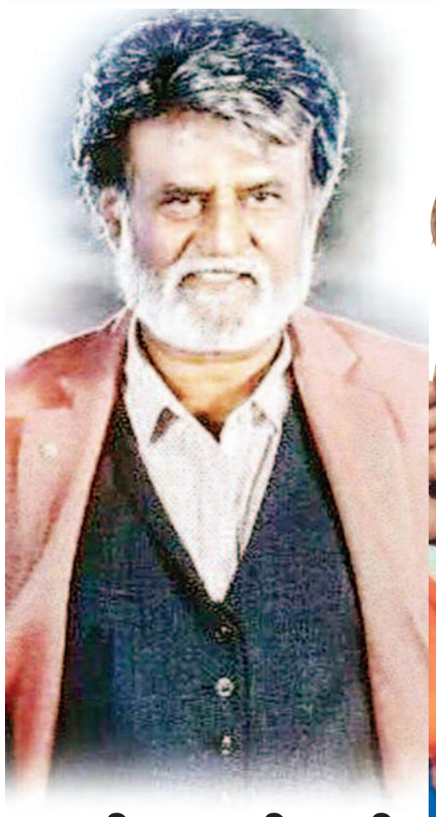

रजनीकांत की कुली को लेकर आया अपडेट, वार 2 के निर्माताओं की बढ़ी चिंताएं

साउथ के सुपर स्टार रजनीकांत की फिल्म कुली को लेकर एक अपडेट सामने आया है। लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म कुली की रिलीज की तारीख का एलान कर दिया गया है। फिल्म 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी।

इस तारीख को रिलीज होगी कुली

ट्वीट में लिखा है कि कुली 14 अगस्त में दुनिया भर में रिलीज होगी। पोस्ट के साथ निर्माताओं ने एक पोस्टर भी जारी किया है। इसमें रजनीकांत सीटी बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुली का वार 2 से होगा टकराव

कुली की रिलीज के एलान से वार 2 के फिल्म निर्माताओं की चिंता बढ़ गई है। इसी तारीख यानी 14 अगस्त को फिल्म वार 2 दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। वार 2 में ऋतिक रोशन और साउथ के सुपर स्टार जूनियर एनटीआर भी हैं। ऐसे में ट्रेड एनालिस्ट अंदाजा लगा रहे हैं कि साउथ में फिल्म वार 2 का कुली के साथ टकराव हो सकता है। ऐसे में साउथ में फिल्म वार 2 का स्कोप खत्म हो गया है। अब देखना ये होगा कि वार 2 के फिल्म निर्माता अपनी फिल्म की रिलीज की तारीख आगे बढ़ाते हैं या फिर तय तारीख पर रिलीज करते हैं।

कुली के बारे में

रजनीकांत की अदाकारी से सजी फिल्म कुली में बॉलीवुड स्टार आमिर खान, टॉलीवुड स्टार नागार्जुन, उपेंद्र, श्रुति हासन, मलयालम अभिनेता सौबिन शाहिर, रेबा मोनिका जॉन और सत्यराज अदाकारी करेंगे। कुली फिल्म को एक एक्शन थ्रिलर माना जा रहा है। इसे लोकेश कनगराज ने लिखा और निर्देशित किया है।

वार के बारे में

फिल्म वॉर 2 2019 में आई ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर स्टारर वॉर की अगली कड़ी है। इस बार भी फिल्म में ऋतिक रोशन अहम भूमिका में होंगे। उनके साथ जूनियर एनटीआर इस बार दो-दो हाथ करते दिखेंगे। इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन और एडवेंचर देखने को मिल सकता है।

तलाक के बाद अब खतरों से खेलती नजर आएंगी धनश्री वर्मा, खतरों के खिलाड़ी 15 का बनेंगी हिस्सा

धनश्री वर्मा का नाम इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद अब खबरें आ रही हैं कि वह रोहित शेट्टी के रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 15 में हिस्सा ले सकती हैं। आइडब्ल्यूएम बज की एक रिपोर्ट के मुताबिक शो के मेकर्स ने धनश्री से संपर्क किया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह इस शो की प्रतियोगी बन सकती हैं।

पहले भी रियलिटी शो में आ चुकी हैं नजर

हालांकि, धनश्री की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। धनश्री पहले भी रियलिटी शो का हिस्सा रह चुकी हैं। साल 2023 में उन्होंने झलक दिखला जा 11 में अपने डांस का हुनर दिखाया था। उस दौरान युजवेंद्र चहल भी शो पर पहुंचे थे और उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया था, लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं।

अलग हो चुकी है धनश्री-चहल की राहें

धनश्री और चहल की शादी 2020 में हुई थी। 18 महीने तक अलग रहने के बाद 20 मार्च 2025 को दोनों का तलाक हो गया। चहल के वकील नितिन कुमार गुप्ता ने एएनआई को जानकारी दी कि कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी है। अब वे दोनों पति-पत्नी नहीं रहे। तलाक के बाद एक और खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि चहल ने धनश्री को चार करोड़ 75 लाख रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देने की सहमति दी थी। इसमें से दो करोड़ 37 लाख रुपये धनश्री को मिल चुके हैं, लेकिन बाकी रकम का भुगतान न होने की वजह से फैमिली कोर्ट ने इसे नियमों का उल्लंघन माना है।

जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं दोनों

धनश्री की बात करें तो वह तलाक के बाद अपने काम में व्यस्त हैं। जिस दिन उनका तलाक हुआ, उसी दिन उनका नया म्यूजिक वीडियो देखा जी देखा मैंने रिलीज हुआ। यह गाना बेवफाई की कहानी बयान करता है। दूसरी ओर, युजवेंद्र चहल भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। तलाक के बाद उन्हें अपनी दोस्त आरजे महवाश के साथ क्रिकेट स्टेडियम में देखा गया। दोनों साथ में मैच का लुत्फ उठाते नजर आए।

लव एंड वार में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण, रणबीर संग करेंगी रोमांस

निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर बहूप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल अहम भूमिकाओं में होंगे। अब, कथित तौर पर दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म में शामिल हो सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेत्री को संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनने वाली फिल्म में एक भूमिका के लिए चुना जा रहा है। फिल्म में दीपिका पादुकोण की रणबीर कपूर के साथ 40 मिनट की भूमिका होगी।

दीपिका रणबीर कर सकते हैं रोमांस

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रणबीर और दीपिका के बीच रोमांटिक सीन भी होंगे। इसलिए फिल्म को सीबीएफसी से ए सर्टिफिकेट मिल सकता है। खबरें ये भी हैं कि फिल्म में भंसाली कैटरीना को भी ले सकते हैं। शायद, एक खास डांस नंबर के लिए!

फिल्म की कहानी के बारे में नहीं है पता

लव एंड वॉर ने रिलीज से पहले ही शानदार चर्चा बटोरी है क्योंकि इसमें कमाल की कास्टिंग है। फिल्म देखने वाले हमेशा संजय लीला भंसाली की फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। हालांकि फिल्म की कहानी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि लव एंड वॉर राज कपूर की फिल्म संगम से प्रेरित है जो एक लव ट्राइएंगल थी।

अगले साल मार्च में रिलीज होगी फिल्म

हम सभी जानते हैं कि रणबीर और दीपिका एक दूसरे को डेट कर रहे थे। बाद में, रणबीर कैटरीना कैफ के साथ रिलेशनशिप में थे, जो अब विक्की कौशल से शादी कर चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में पहले से ही रणबीर की रियल लाइफ पत्नी आलिया भट्ट हैं। लव एंड वार अगले साल मार्च में रिलीज हो सकती है। उम्मीद है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काई अच्छा कमाल करेगी।

छावा के बाद अक्षय खन्ना के हाथ लगा बड़ा प्रोजेक्ट

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा में औरंगजेब के किरदार से सबका हैरान कर देने के बाद अब वह अपनी अगली बड़ी फिल्म के साथ तैयार हैं। अक्षय ने प्रशांत वर्मा की फिल्म महाकाली साइन की है। यह फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स (पीवीसीयू) की तीसरी कड़ी होगी। फिल्म का निर्देशन पूजा अपर्णा कोल्लुरु कर रही हैं।

महाकाली में दिखेंगे अक्षय खन्ना

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने लिखा कि अक्षय खन्ना महाकाली में एक अहम भूमिका निभाएंगे। यह फिल्म आरकेडी स्टूडियोज के बैनर तले बन रही है। हनु-मान की शानदार सफलता के बाद अब महाकाली इस यूनिवर्स की अगली सुपरहीरो फिल्म होगी। यह एक पैन-इंडिया प्रोजेक्ट है जो देशभर के दर्शकों तक पहुंचेगा।

बंगाल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर होगी फिल्म

महाकाली खास इसलिए है, क्योंकि यह भारत की पहली महिला सुपरहीरो फिल्म होगी। फिल्म की कहानी बंगाल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। लीड रोल में एक सांवली अभिनेत्री नजर आएगी। यह फिल्म सामाजिक संदेश के साथ भारतीय सिनेमा में सौंदर्य मानकों को फिर से परिभाषित करने की कोशिश करेगी।

2024 में हुआ था एलान

फिल्म का बैकग्राउंड बंगाल का है, जहां मां काली की पूजा गहरी आस्था के साथ होती है। 2024 में इसकी घोषणा हुई थी। महाकाली में बंगाल की परंपराओं और वहां की मिट्टी की खुशबू दिखेगी। फिल्म के निर्माता शानदार विजुअल्स और भावनात्मक कहानी के जरिए लोगों का दिल जीतने की कोशिश में हैं।

क्या हॉलीवुड जाने की तैयारी में हैं ऋतिक? क्रिस्टोफर नोलन संग काम करने की जताई इच्छा

एक्टर ऋतिक रोशन अभिनय के बाद अब निर्देशन की दुनिया में अपना हुनर दिखाएंगे। हाल ही में उनके पिता व निर्देशक राकेश रोशन ने एलान किया कि कृष 4 के निर्देशन की कमान ऋतिक रोशन संभालेंगे। इससे उनके फैंस का उत्साह चरम पर है। दूसरी तरफ, ऋतिक अपनी आगामी फिल्म वॉर 2 को लेकर भी खूब चर्चा बटोर रहे हैं। इस बीच उनके हॉलीवुड में काम करने की चर्चा शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत एक्टर के एक बयान के बाद शुरू हुई है। दरअसल, हाल ही में एक इवेंट के दौरान ऋतिक रोशन ने ब्रिटिश अमेरिकी निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है। ऐसे में ऋतिक के फैंस भी चाहते हैं कि पसंदीदा अभिनेता की यह मुराद जल्द पूरी हो। भारतीय इंडस्ट्री में 25 वर्ष पूरे करने पर अटलांटा में अपने यूएसए टूर के दौरान, ऋतिक रोशन ने ब्रिटिश-अमेरिकी निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम करने जताई है। अकादमी पुरस्कार विजेता निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की तारीफ करते हुए ऋतिक ने कहा कि वे उनके फेवरेट निर्देशक हैं। बता दें कि क्रिस्टोफर नोलन मोमेंटो (2000), द डार्क नाइट ट्रिलॉजी (2005-2012), इनसेप्शन (2010), इंटरस्टेलर (2014) जैसी फिल्मों के लिए मशहूर हैं। उनकी पिछली चर्चित फिल्म ओपेनहाइमर (2023) है, जिसके लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार मिला।

मैं अपनी शादी को असफल नहीं मानता, बरखा बिष्ट से तलाक पर इंद्रनील ने बात की

इंद्रनील सेनगुप्ता और बरखा बिष्ट अब शादीशुदा जिंदगी में नहीं हैं। साल 2022 में दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को खत्म कर तलाक ले लिया। बीते दिनों बरखा ने एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई बातें शेयर कीं। इस दौरान उन्होंने इंद्रनील के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी का भी जिक्र किया। उन्होंने इंद्रनील पर चीटिंग करने का आरोप लगाया। वहीं, इंद्रनील का मानते हैं कि बरखा के साथ उनकी शादी असफल नहीं रही।

तलाक ने सकारात्मक रूप से बदला

बरखा बिष्ट के चीटिंग के आरोपों के बीच हाल ही में इंद्रनील सेनगुप्ता ने बरखा के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी पर बात की। उन्होंने यह भी बताया कि अलगाव के बावजूद वे अपनी शादीशुदा जिंदगी को असफल क्यों नहीं मानते हैं? एक पॉडकास्ट में इंद्रनील ने अपनी शादी को लेकर बात की और कहा कि तलाक ने उन्हें सकारात्मक तरीके से बदला है।

शादी में कई खूबसूरत पल आए

इंद्रनील सेनगुप्ता ने संघमित्रा हितैषी के पॉडकास्ट पर बताया कि बरखा बिष्ट से तलाक का उनके जीवन पर क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ा? उन्होंने अपने अलगाव के बाद अपनी पर्सनल ग्रोथ पर बात की। इंद्रनील ने कहा कि कुछ लोग बरखा के साथ उनकी शादी को असफलता मान सकते हैं। हालांकि, उनका मानना है कि यह शादी 13 वर्षों तक सफल रही। उन्होंने इस बारे में कहा कि दोनों की शादीशुदा जिंदगी में कई अच्छे पल आए, कुछ बहुत अच्छे पल आए और कुछ चुनौतीपूर्ण पल भी रहे।

2008 में हुई कपल की शादी

इंद्रनील ने आगे कहा कि वे अपनी शादी को असफल नहीं कहना चाहेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी और बरखा की यात्रा किस तरह व्यक्तिगत रही। और किस तरह बदलाव आए। उन्होंने कहा, कभी-कभी व्यक्तित्व बदल जाते हैं। हम पहले दिन से ही अलग लोग थे। जैसे-जैसे साल बीतते गए, हम खुद से ज्यादा अलग होते गए। मैं असफलता शब्द से सहमत नहीं हूं। कोई भी चीज असफल नहीं होती। बता दें कि बरखा और इंद्रनील की शादी साल 2008 में हुई। 2011 में कपल ने बेटी का स्वागत किया। तलाक के बाद बेटी बरखा के साथ रहती है।

इस खास दिन पर रिलीज होगी चिरंजीवी की विश्वंभरा!

विश्वंभरा चिरंजीवी की बहुप्रतीक्षित फिल्म है, जिसकी रिलीज डेट के एलान का इंतजार फैंस को बेसब्री से है। इस फिल्म के जरिए चिरंजीवी और निर्देशक वशिष्ठ मल्लिदी पहली बार साथ काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, विश्वंभरा 24 जुलाई, 2025 को रिलीज हो सकती है यह तारीख मेगा प्रशंसकों के लिए विशेष महत्व रखती है, जिसके पीछे की वजह चिरंजीवी ही है। दरअसल, यह चिरंजीवी की हिट फिल्म इंद्र (2002) की रिलीज की सालगिरह है। हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट पर निर्माताओं की ओर से आधिकारिक एलान का इंतजार है। फिल्म में तृषा, आशिका रंगनाथ, कुणाल कपूर, राम्या पसुपलेटी, ईशा चावला और आश्रिता वेमुगंती नंदूरी भी हैं।

स्वामी मुद्रक,प्रकाशक पीतम सिंह द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस,डी-85 सेक्टर-6 नोएडा गौतमबुद्धनगर से मुद्रित करवाकर मकान नं.-57 सोरखा, जाहिदाबाद सेक्टर-115 नोएडा गौतमबुद्धनगर से प्रकाशित किया। **RNI.NO.UPHIN/2010/31600** इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन व संपादन हेतु पीआबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी। सभी विवादों का न्याय गौतमबुद्धनगर न्यायालय के अधीन होगा। **संपादक (प्रमोद यादव) मो.9999164275, E-editorsaimedia@gmail.com**